चौथी दुनिया

दिल्ली, 18 अप्रैल-24 अप्रैल 2011

www.chauthiduniya.com

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र

सब कुछ फिक्स्ड है

विधानसभा के बजट सत्र में बजट को लेकर कोई चर्चा नहीं होती. बस एक-दो दिन औपचारिक प्रतिक्रियाएं और आरोप-प्रत्यारोपों का दौर. सत्र दर सत्र यही होता है. असल मुद्दे से भटक कर विपक्ष और सत्ता पक्ष विधान मंडल का कामकाज नहीं होने देते हैं. क्या इसीलिए बजट सत्र रखा जाता है.

प्रवीण महाजन

क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बीच जब महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा हो और उसमें मैच फिक्सिंग की तर्ज़ पर सब कुछ फिक्स दिखे तो किसी को आश्चर्य नहीं होता है. कारण भी साफ़ है. एक या दो बार हो तो समझ में आता है, लेकिन सत्र दर सत्र अगर सत्र समाप्ति के बाद विश्लेषकों को एक ही पैटर्न दिखे तो फिक्सिंग की सुगबुगाहट होना लाज़िमी है. सत्र अंतिम पड़ाव तक आने के पहले तक काफ़ी हंगामेदार रहा. यह सुनकर लगता है कि सत्र में विपक्ष हावी रहा, लेकिन अंत में सब कुछ टांय-टांय फिस्स. संजय गांधी निराधार योजना के मामले में विपक्ष का हंगामा और सदस्यों का निलंबन. फिर हसन अली मामले में स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पुलिस अधिकारी का निलंबन और देश के पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त थॉमस मामले में मुख्यमंत्री से इस्तीफ़े की मांग. यानी बजट सत्र महाराष्ट्र का. इसमें बजट को लेकर कोई चर्चा नहीं. बस एक-दो दिन औपचारिक प्रतिक्रियाएं और आरोप-प्रत्यारोपों का दौर. सत्र दर सत्र यही होता है. असल मुद्दे से भटक कर विपक्ष और सत्ता पक्ष विधान मंडल का कामकाज नहीं होने देते. आज़ादी के बाद जब नागपुर को सेंट्रल प्रॉविन्स की राजधानी बनाया गया और फिर महाराष्ट्र में शामिल किया गया तो नागपुर क़रार किया गया था. इस क़रार के अनुसार नागपुर में शीतसत्र होता है. इस सत्र में विदर्भ की समस्याओं का समाधान अपेक्षित होता है, लेकिन होता क्या है, यह सबके सामने है. विदर्भ की चर्चा सिर्फ़ एक या दो दिन ही होती है. वह भी किसी मंत्री विधायक के किसी बयान के बाद हंगामे में बदल जाती है. लोकतंत्र की यह बड़ी विडंबना है कि लोक और तंत्र दोनों होने के बावजूद लोकतंत्र की मूल भावना की ही उपेक्षा कर दी जाती है.

बजट सत्र के एक दिन पहले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा आयोजित चाय पार्टी का पूरे विपक्ष ने बहिष्कार कर यह संकेत देने का प्रयास किया था कि इस बार वह सत्तापक्ष की कड़ी अग्निपरीक्षा लेने के लिए तैयार है. विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन ही भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए माफ़िया राज हटाओ रैली का आयोजन करके विधानसभा के माहौल को काफ़ी गरमा दिया. रैली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के नेतृत्व में संपन्न हुई और इसमें राष्ट्रीय महासचिव गोपीनाथ मुंडे सहित महाराष्ट्र के कोने-कोने से आए बड़ी तादाद में भाजपा के लोगों ने हिस्सा लिया. इस सफल रैली में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माफ़िया व गुंडाराज को हटाने का संकल्प लिया. शिवसेना अध्यक्ष बाला साहेब ठाकरे के परिवार की नई युवा पीढ़ी के सदस्य आदित्य ठाकरे ने विधानसभा परिसर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. बजट सत्र की शुरुआत के पहले हफ्ते में विपक्ष सत्तापक्ष पर हावी रहा. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पी.जे. थॉमस की नियुक्ति एवं आदर्श घोटाले में चल रही जांच की धीमी कार्रवाई विपक्ष के ऐजेंडे में शीर्ष पर रही. बजट सत्र के दूसरे सप्ताह में उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला बजट विधानसभा में रखा. मगर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कोई उनका भाषण सुन न सका. विपक्षी सदस्यों ने सरकार के विरोध में पोस्टरों और बैनरों का भी उपयोग किया व विधानसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और कई बार स्थगित करना पड़ा. संजय गांधी निराधार योजना को तहसील स्तर पर लागू करने वाली समिति के अध्यक्ष, पहले विधायक हुआ करते थे. मगर पिछले साल सरकार ने उनसे यह अधिकार छीन लिया. इससे नाराज़ विपक्ष ने अधिकार वापस किए जाने की मांग को लेकर भारी नारेबाज़ी की. अजीत पवार जब बजट पेश कर रहे थे, उस समय विरोधी पक्ष के विधायक हंगामा कर रहे थे. इसके बाद विपक्ष के 9 विधायकों को निलंबित कर दिया गया. इनमें विधायक विनोद घोसालकर (दहिसर), एकनाथ शिंदे (कोपरी-पाचपाखाड़ी), विजय शिवतारे (पुरंदर), रविंद्र वायकर (जोगेश्वरी-पूर्व), प्रताप सरनाइक (ओवला-माजिवाड़ा), सरदार तारासिंह (मुलुंड), विजय देशमुख (सोलापुर-शहर उत्तर), हरीश पिंपले (मूर्तिजापुर) और गिरीश महाजन (जामनेर) शामिल थे. इस निलंबन की कार्रवाई पर भी राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि इन विधायकों ने सिर्फ़ नारेबाज़ी कर शोर-शराबा किया था. विधानसभा के सभागृह में संपत्ति को नुक़सान पहुंचाने, मंत्री और सत्ताधारी विधायकों पर हमले का प्रयास करने, सामान फेंककर शारीरिक कष्ट देने, गाली-गलौज करने की हद तक तो कोई भी विधायक नहीं गया था. ऐसी स्थिति में शिवसेना के पांच और भारतीय जनता पार्टी के चार विधायकों को दिसंबर तक के लिए निलंबित करने का निर्णय लेना आश्चर्यजनक था. यह निर्णय वापस ले लिया गया. हालांकि तकनीकी दृष्टि से यह निर्णय सभागृह का था तथा यह सत्ताधारी आघाड़ी के नीतिगत निर्णय का भाग था, लेकिन इस कार्रवाई को अजीत पवार की व्यक्तिगत आकांक्षा के रूप में प्रसारित कर दिया गया. दूसरी ओर नारेबाज़ी में शामिल होने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायकों पर निलंबन कार्रवाई नहीं हुई थी. इसके अलावा बजट के दूसरे दिन उपद्रव मचाने वाले विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर सत्ताधारी आघाडी के विधायकों ने नारेबाज़ी कर कामकाज बंद कर दिया था. मनसे विधायकों को कार्रवाई से बचाकर विरोधियों में फूट डालने की राजनीति नज़र आई, लेकिन इस मामले में विधानसभा के कामकाज का बहिष्कार करने के शिवसेना, भाजपा और मनसे के नेताओं के एकत्रित निर्णय ने सत्ताधारियों की इस चाल पर पानी फेर दिया.

निलंबन के बाद यह लगातार प्रचारित किया जाता रहा कि मुख्यमंत्री निलंबन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अजीत पवार की ज़िद के कारण यह करना पड़ा. वैसे राज्य में अजीत पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद से राकां के लगातार बढ़ते प्रभाव से कांग्रेस ख़ासी परेशान है और येन-केन-प्रकारेण वह इस पर लगाम लगाना चाहती है. एक समय कांग्रेस का गढ़ रह चुका सतारा ज़िला इस समय राकां के क़ब्ज़े में है. यहां ज़िला परिषद की अधिकांश पंचायत समितियों, पालिकाओं और ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का परचम लहरा रहा है. इस पर पुनः अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कांग्रेस में मोर्चेबंदी जारी है. बहुसंख्य स्थानीय स्वराज संस्थाओं वाले ज़िला परिषद, पंचायत समिति और नगरपालिकाओं के आगामी चुनाव साल भर बाद होने वाले हैं. इस चुनावों में अपना झंडा फहराने के लिए कांग्रेस ने साल की शुरुआत से ही अपनी गतिविधियां तेज़ कर दी हैं. सतारा ज़िले में आठ विधायक हैं. शिवेंद्र सिंहराजे भोसले, शशिकांत शिंदे, दीपक चव्हाण, विक्रमसिंह पाटणकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं. मकरंद पाटिल और बालासाहब पाटिल राकांपा के दो प्रभावशाली विधायक हैं. विलासराव पाटिल-उंडालकर ही कांग्रेस से चुनकर आए हैं. इनके अलावा फलटण के रामराजे नाईक-निंबालकर विधान परिषद में राष्ट्रवादी से गए हैं. राकांपा के ही प्रभाकर घार्गे स्थानीय स्वराज्य संस्था से विधान परिषद पहुंचे हैं.

कुल मिलाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता यहां फलफूल रही है. राकांपा के इस साम्राज्य को हथियाने के मंसूबे कांग्रेस के खेमे में पल रहे हैं. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण करहाड के होने के कारण उनके नेतृत्व में यहां पार्टी का पुनर्गठन

(शेष पृष्ठ 18 पर)

बजट सत्र के दूसरे सप्ताह में उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने अपने राजनैतिक जीवन का पहला बजट विधानसभा में रखा, मगर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कोई उनका भाषण सुन न सका. विपक्षी सदस्यों ने सरकार के विरोध में पोस्टरों और बैनरों का भी उपयोग किया एवं विधानसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और कई बार उसे स्थगित करना पड़ा.

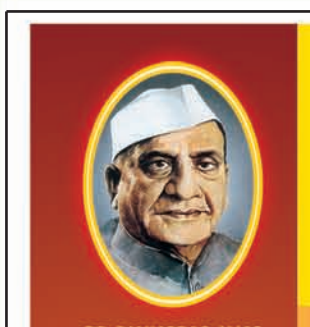

DR. PANJABRAO ALIAS BHAUSAHEB DESHMUKH
Founder President
Shri Shivaji Education Society, Amravati

Adv. Arunkumar Shelke
President
Shri Shivaji Education Society, Amravati

Dr. B. B. Taywade
Principal
Dhanwate National College Nagpur.

Shri Shivaji Education Society, Amravati s
(An establishment with more than 260 Educational Institute in Vidarbha)

Dhanwate National College

Congress Nagar, Nagpur. (Established in 1935)
Phone: (0712) 2422759, 2454193, Fax: (0712) 2454193
E-mail: dhanwatenationalcollege@yahoo.com Website: www.dncnagpur.com

B++ Accredited by NAAC, Bangalore
'College With Potential For Excellence' status by UGC
Recipient of Special Grant from UGC for being *Old & Reputed* College

Courses Offered

● B.A. (Marathi Medium) ● B.Com. (English & Marathi Medium) ● B.Com. (Computer Application) ● B.B.A. (Bachelor of Business Administration) ● M.A. (Economics, English, Marathi, Sociology, Geography) ● M.Com. ● PGDCCA (Post Graduate Diploma in Computer Commercial Application) ● MCM (Master of Computer Management) ● DBM (Diploma in Business Management) ● DIRPM (Diploma in Industrial Relation & Personnel Management) ● MIRPM (Master of Industrial Relation & Personnel Management) ● BJ (Bachelor of Journalism) ● M.A. (Mass Communication) ● PGDGIS (Post Graduate Diploma in GeoInformatics) ● M.Phil. (Commerce) ● XI, XII (Arts (Marathi Medium), Commerce (English & Marathi Medium), MCVC) ■ Recognized Center for Ph.D. Programme of RTM Nagpur University

Dr. Panjabrao Deshmukh Institute of Management Technology and Research Dhanwate National College, Nagpur
Phone: (0712) 2430464, 2445356, Fax : (0712) 2454193
E-mail: pdimtr@rediffmail.com, Website: www.pdimtr.co.in

Master of Business Administration (M.B.A.)

Salient Features

- Sprawling Campus with separate playgrounds for different Outdoor Sports & independent Cricket Ground.
- Rich Central Library and independent study center.
- State of Art Computer Laboratory with Wi-Fi Facility.
- Fully Air Conditioned and Spacious classrooms.
- Auditorium with more than one thousand audiences capacity.
- Highly qualified and dedicated teaching staff with three generations being recipient of the Best Teacher's Award of State Government.
- Initiator of Campus Placement Culture at UG Level in this region.
- Consistent organiser of State, National and International Level Academic & Sports Events.
- Special emphasis on total personality development through academic, cultural and social activities.
- Special motivation to Sports.

Courses Offered

Add-On Courses as per UGC Scheme (Certificate / Diploma / Advance Diploma)
- E-Commerce & Business Outsourcing
- Computer Applications for Business
- Intellectual Property Rights
- Data Base Administration (DBA)

Under Jeevan Shikshan Abhiyan of RTM Nagpur University
- English written & Communication Skill
- Applied Accounting and Finance
- Certificate Course in Rashtrasant Tukdoji Maharaj Thoughts

MES Courses under GOI Scheme
- Computer Fundamental MS-Office & Internet
- Tally 9.0
- 2- D Pre Production Animator
- Mass Communication
- Basic Food Preservation

Diploma in Banking and Finance (DBF) Course of IIBF

YCMOU Courses

● MBA ● B.Com. ● B.A. ● Preparatory

* For Further details refer College Prospectus.

यह कोई पहली बार नहीं है. इसके पहले भी भाजपा और आरएसएस के कई दिग्गज उनकी वापसी को लेकर कई बार स्तर पर विचार-विमर्श कर चुके हैं.

उमा भारती
नागपुर से बैरंग वापस

जागो हिन्द संगठन एवं किसान संघर्ष मोर्चा की एक संगोष्ठी में भाग लेने के दौरान संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में उमा भारती ने जिस हिम्मत के साथ कहा था कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में वह एक ब्लैंक चेक की तरह हैं, जिसे पार्टी जैसे चाहे कैश करा ले, उसकी आज़माइश क़रीब आ गई .

क्रिकेट मैच की तरह अगर सटोरिए उमा भारती की भाजपा वापसी पर सट्टा लगाते पकड़े गए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है. उमा भारती भोपाल से काफ़ी ख़ुश होकर नागपुर के लिए निकली थीं. मीडिया उनके इस प्रवास पर पैनी नज़र रखे हुए था. रात की नीरवता में साध्वी सधे कदमों से गडकरीवाड़ा पहुंचती हैं और औपचारिक बातचीत के बाद रविभवन की ओर निकल जाती हैं. अगले दिन समाचार-पत्रों के पन्ने साध्वी के सधे क़दमों की आहट लोगों तक पहुंचा देते हैं. आनन-फानन में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की कमान उमा को थमाने की बातें बतौर घोषणा प्रकाशित की जाती है. मगर यहां एक चूक हो गई. दरअसल, इसके बात पीछे कोई नहीं गया कि साध्वी को नागपुर में इस बार रुकना तो मात्र एक दिन था, 3 दिनों का कार्यक्रम कैसे बन गया? अगले दिन संघ के वरिष्ठ नेताओं से बात के बाद भी वापसी की घोषणा क्यों नहीं हुई?

यह कोई पहली बार नहीं है. इसके पहले भी भाजपा और आरएसएस के कई दिग्गज उनकी वापसी को लेकर कई बार स्तर पर विचार-विमर्श कर चुके हैं. कई बार ऐसा लगा कि बस औपचारिक घोषणा ही शेष है, लेकिन दिल्ली की नकेल के चलते उमा फिर हाशिए पर चलीं जाती हैं. देखा जाए तो भाजपा मे उमा भारती की भाजपा में जितनी उठापटक, जितने दांवपेच एवं जितनी राजनीति चल रही है, वह शायद ही किसी भी दल में किसी भी नेता की वापसी को लेकर हुई हो. नाटकीय राजनीति का यह एक और नाटकीय अल्पविराम. गत 26 दिसंबर को अपनी नागपुर यात्रा के बाद उमा भारती ने कहा कि वह भाजपा में वापस नहीं आ रही हैं. बीच में फिर नितिन गडकरी ने कहा कि वह जब चाहें भाजपा में वापस आ सकती हैं. फिर क्या हुआ?

उनकी भाजपा में वापसी की ख़बर इतनी दफ़ा अख़बारों में प्रकाशित हो चुकी है कि राजनीतिक विश्लेषक भी परेशान हो गए हैं. पहले उनकी वापसी की ख़बर छपती है, फिर खंडन. आख़िर उमा भारती भाजपा में वापस क्यों नहीं आतीं? या फिर वे कौन हैं जो उन्हें आने नहीं देते? क्या उमा भारती चाहती हैं कि उन्हें गाजे-बाजे के साथ पार्टी में वापस लाया जाए या फिर भाजपा के गद्दीनशीन नेता उमा भारती को घुटने के बल रेंगते हुए पार्टी में लाना चाहते हैं. वैसे उमा भारती के तेवर ख़ुद उमा के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहे. अपनी आक्रामक प्रवृत्ति के कारण उनकी कभी किसी से लंबे समय तक नहीं बनी है. अंगद के पांव की तरह जमकर मध्य प्रदेश में शासन कर रहे दिग्विजय सिंह को 2003 के विधानसभा चुनाव में धूल चटाकर भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली साध्वी आज अपने लोगों के लिए ही भूत (बीती हुई नेत्री) हो गई हैं. भूत (डरावनी) इसलिए भी कि अब उनकी वापसी की ख़बर मात्र से ही लोग डर जाते हैं. दिल्ली के हाईटेक नेताओं का रक्तचाप बढ़ जाता है. जब-जब उमा भारती की भाजपा में वापसी की बयार बहती है, उमा विरोधी सर उठाकर खड़े हो जाते हैं. मगर भाजपा को उत्तर प्रदेश में सड़क पर ला देने वाली मायावती की असली राजनीतिक काट के रूप में भाजपा के पास उमा के अलावा और कोई नहीं हो सकता. सब जानते हैं कि उमा का किनसे और क्यों छत्तीस का आंकड़ा है. भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में जो लोग राज कर रहे हैं, उनमें वह सबसे ज़्यादा हावी हैं जो लोकसभा चुनाव में अपने कर्मों से भारी अंतर से हारे हुए हैं या जिनका कोई ख़ास जनाधार नहीं है. कुछ हाईटेक नेता भी हैं. पहले चार थे और अब इसे तिकड़ी के नाम से जाना जाता है. ये जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कथित तौर पर योग्य मगर पिटे हुए मोहरे कहलाते हैं. इस बार तो ऐसा लगा कि उमा और भाजपा में पटरी बैठ गई है, लेकिन बाबा रामदेव की रैली ने भंडाफोड़ कर दिया. भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी और मा.गो. वैद्य सहित अन्य नेताओं से मुलाकात के बाद बताया गया कि साध्वी परोक्ष रूप से भाजपा की मदद करेंगी और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से होगी. इसके पहले बाबा रामदेव की नागपुर में 24 मार्च को होने वाली रैली को दौरान मंच पर उपस्थित होना था, लेकिन साध्वी 22 मार्च को ही रात में नागपुर से रवाना हो गईं. अब यहां सवाल उठना लाजिमी है कि उमा भारती ने आख़िर ऐसा क्यों किया? या फिर ऐसा करने के लिए वह क्यों मजबूर हुईं? कयास और हक़ीक़त के बीच कारणों पर मंथन जारी है. होली में जब सारा आलम रंगों से सराबोर था, उमा भी भगवा रंग में रंगने नागपुर ठीक ही पहुंची थीं. कथित तौर पर संघ और भाजपा अध्यक्ष ने एक तीर से दो शिकार किए. उत्तर प्रदेश में भाजपा की नैया को पार लगाने में अहम भूमिका अदा करने के लिए कहा. रणनीति थी कि उमा कामयाब रहीं तो गडकरी अपना लोहा मनवा लेंगे और अगर इसके उलट हुआ तो उमा शेखी बघारना छोड़ देंगी. इस तरह भाजपा अध्यक्ष के दोनों हाथ में लड्डू हैं जबकि उमा भारती के लिए अग्निपरीक्षा से कम नहीं. जागो हिन्द संगठन एवं किसान संघर्ष मोर्चा की एक संगोष्ठी में भाग लेने के दौरान संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में उमा भारती ने जिस हिम्मत के साथ कहा था कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में वह एक ब्लैंक चेक की तरह हैं, जिसे पार्टी जैसे चाहे कैश करा ले, उसकी आज़माइश क़रीब आ गई. भाजपा के सामने वर्ष 2014 का आम चुनाव एवं उससे पहले 2012 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सामने है. ख़ुद नितिन गडकरी के लिए भी यह किसी चुनौती से कम नहीं. मिशन की पूर्णता के लिए सुनियोजित ढंग से कोर्ट में उमा भारती को उतारने की कवायद अंतिम चरण में थी. पार्टी अध्यक्ष जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई इबारत लिखने के लिए उमा सबसे योग्य हैं. उमा मध्य प्रदेश की हैं और सदैव ही संघ एवं भाजपाइयों से उनका संबंध रहा है. वह मुखर, वाचाल एवं विस्फोटक नेत्री हैं. महिला और पिछड़े वर्ग का फ़ायदा उठाने के लिए यह चेहरा सर्वथा अनुकूल है तो राजनीतिक वनवास से निकलने की छटपटाहट भी है. ग्वालियर में बहिन की नातिन का एक क़रीबी प्रीतम लोधी के बेटे के साथ ब्याह का मौक़ा था. पूरा माहौल उत्साह और उमंग से लबरेज था. गीतों की धुन पर हर कोई थिरक रहा था. कुछ महिलाओं ने उमा भारती को भी घेर लिया. इस दौरान फिल्म यमला पगला दिवाना के गीत टिंकू जिया की धुन उमा को इतनी भायी कि वह अपने को रोक न सकीं. राजनीतिक खेमे में खलबली मच गई. जिन्होंने उस फुटेज को देखा, सपाट कहा कि तल्ख बयानी के कारण चर्चाओं में रहने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मन की मालकिन हैं और वह ख़ुद को सीमाओं में बांधकर भी नहीं रखतीं. मगर मजबूरी स्वभाव से कभी-कभी दूर कर देती है. उमा भी अपने स्वभाव से इन दिनों दूर हैं. दिल्ली की तिकड़ी भारी पड़ रही है. उमा की नागपुर से बैरंग वापसी मिशन उत्तर प्रदेश के लिए ख़तरनाक संकेत हो सकता है.

श्वेता सिन्हा
feedback@chauthiduniya.com

जननी सुरक्षा योजना

"मातामृत्यु व बालमृत्यु टाळण्यासाठी, जननी सुरक्षा योजनेचा फायदा घ्या."

NRHM
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान
महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग

- या योजनेचा लाभ दारिद्रय रेषेखालील तसेच अनुसुचित जाती व जमातीतील मातांना घेता येईल.
- ग्रामीण व शहरी भागातही ही योजना कार्यान्वित आहे.
- लाभार्थी महिलेचे वय प्रसवपूर्व नोंदणी करतांना कमीत कमी १९ वर्षे असावे.
- ग्रामीण क्षेत्रामध्ये बाळंपणसाठी शासकीय ग्रामीण आरोग्य संस्थेत लाभार्थी आल्यावर व प्रसुती झाल्यावर रु ७००/- अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात येईल.
- शहरी क्षेत्रामध्ये बाळंपणकरीता शासकीय/स्थानिक आरोग्य संस्थेत लाभार्थी आल्यावर व प्रसुती झाल्यावर रु. ६००/- अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात येईल.

"जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी"
आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, नागपूर.

Heartiest congratulations
on Inauguration
of
Maharashtra Edition
of
National weekly Newspaper
चौथी दुनिया
Mr. Vijay Poharkar
SHANTI
Construction Co.
Lakhani

मिपरी से लोणी तक के 4 किमी के रास्ते पर काम चालू है, साथ ही उखड़ता भी जा रहा है. हाईवे से आजगांव तक का 1.2 किमी लंबा रास्ता ठीक नहीं बनाया गया है.

पूनम को अपने पहले चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा. इस समय पूनम महाजन भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अपनी पार्टी के लिये काम कर रही हैं.

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र

सब कुछ फिक्स्ड है

पृष्ठ 17 का शेष

करने और इसके माध्यम से राकांपा के पर कुतरने का प्रयास कांग्रेस के स्थानीय नेता कर रहे हैं. कांग्रेस ने अपने प्रयासों की श्रृंखला में ही फलटण सहित ज़िले के अन्य भागों में मतदाताओं को जागरूक करने की एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें चव्हाण भी अपनी हाजिरी लगा चुके हैं. सतारा में भ्रमण कर कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी पिछड़े वर्ग के युवाओं से संवाद भी साध चुके हैं. इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार, अजीत पवार, आरआर पाटिल का भी ज़िले में दौरा हुआ, कार्यक्रम हुए. ख़ैर, सतारा में वर्चस्व की इस लड़ाई का ज़िक्र करना इसलिए सामयिक था, क्योंकि इसका असर विधान मंडल में भी देखा गया. जब विपक्ष के विधायक विधानभवन परिसर में नारेबाज़ी कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उस समय उनका तीर कांग्रेस–राकां गठबंधन पर ख़ूब चला. नारे लगे कि कांग्रेस विपक्ष के साथ है. इस प्रकरण के बाद विधान परिषद में विरोधी पक्ष के नेता पांडुरंग फुंडकर ने एक समाचार पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राज्य के 3 मुख्यमत्रियों के काले धन को व्यवस्थित करने का काम पुणे से गिरफ्तार व्यवसायी हसन अली करता था और उसने इनके पैसों को शेयर बाज़ार में लगाकर विदेशी बैंकों में जमा किया. सत्ता पक्ष द्वारा उनके इस बयान का ज़ोरदार विरोध किया गया और कहा गया कि किसी पेपर में छपे लेख के आधार पर सदन में इस प्रकार का आरोप लगाना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है. इसी मामले पर बोलते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने राज्य के गृहमंत्री आर.आर. पाटिल पर हमला बोलते हुए कहा कि डीसीपी अशोक देशभ्रतार को निलंबित करना ग़लत है. क्योंकि उनकी 28 साल की नौकरी में एक भी दाग़ नहीं है. उन्होंने व्यापारी हसन अली को गिरफ्तार किया और पूछताछ की जिसकी बनी हुई सीडी में अफसरों और नेताओं का नाम सार्वजनिक होने से रोकने के लिये ही उन्हें निलंबित किया गया. गृहमंत्री आर.आर. पाटिल भी पीछे नहीं रहे और देशभ्रतार के निलंबन को जायज़ ठहराते हुए कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जो सीडी बनाई गई थी, वह बोगस है और उसमें बनावटी जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ सरकार व उसके कुछ नेताओं को बदनाम करने की नीयत से बनाई गई है. मगर उन्होंने यह माना कि सीडी में जो आवाज़ है वह हसन अली की ही है. इस सबके बीच सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में जहां पिछले साल 5,688 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था. सिर्फ़ विपक्ष ही नहीं, दबी जुबान से कांग्रेस ने भी इसे राकांपा का बजट क़रार दिया. कुछ घंटे तक सधी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती रही. बाद में विधान मंडल में हंगामे पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया. इस बजट में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, ने 58 करोड़ रुपये का फ़ायदा दिखाया. बजट में ग्रामीण क्षेत्रों व किसानों के लाभ का ख्याल रखा गया है क्योंकि अगले साल स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं. बजट पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की प्रतिक्रिया ज़रूर सकारात्मक रही और उन्होंने बजट को आम आदमी, ग्रामीण और किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट निरूपित किया. बजट में हर महकमे को उसकी मांग से ज़्यादा धन आंवटित किया गया है. जहां किसानों को 50 हज़ार रुपये तक शून्य दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं अल्पसंख्यकों के लिये 275 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है. विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि 58 करोड़ रुपये का फ़ायदा आकड़ों की बाजीगरी है. सच्ची बात यह है कि प्रदेश क़र्ज़ के जाल में डूबता जा रहा है. उन्होंने कहा कि आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है. उसमें राहत के लिये सरकार ने कोई योजना पेश नहीं की है. प्रदेश की क़ानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र की स्थिति बिहार से भी बदतर हो गई है.

इस बजट सत्र में विपक्ष आक्रामक रहा. अजीत पवार ने तेवर ज़रूर दिखाए परन्तु सामान्य तौर पर सरकार बचाव की मुद्रा में ही रही. मगर दोनों पक्ष जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि राज्य में बिजली की समस्या, महंगाई, औद्योगिक उत्पादन, कृषि की स्थिति पर न सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष ने कोई सार्थक बहस की. महत्वपूर्ण समय पक्ष–विपक्ष ने आपसी आरोप–प्रत्यारोप में ही बर्बाद किया. प्रदेश की सारी समस्याएं जस की तस हैं.

feedback@chauthiduniya.com

राजनीतिक विरासत संभालते युवा चेहरे

रवि मिश्रा

आमतौर पर भारत में राजनीतिक वंशवाद को लोकतंत्र के लिए नासूर ही माना जाता है, लेकिन इस स्याह पक्ष के अलावा हक़ीक़त की एक दूसरी ज़मीन भी है. ख़ासकर तब, जबकि राजनीति की विरासत को संभालना आसान काम नहीं है. वह भी जब कोई कद्दावर नेता हो तो उसकी विरासत को उसी रूप में सहेज कर रखना तो मुश्किल ही है पर महाराष्ट्र में कई ऐसे लोग हैं, जो आज न सिर्फ़ राजनीति की विरासत को संभाल रहे हैं बल्कि राजनीति के नए मायने भी स्थापित कर रहे हैं. इस आलेख में आपको महाराष्ट्र के कुछ ऐसे ही राजनीतिक उत्तराधिकारियों से रूबरू करा रहे हैं.

आदित्य ठाकरे – पुत्रों की जमात में 20 वर्षीय आदित्य ठाकरे सबसे युवा चेहरे हैं. 17 अक्टूबर 2010 को विजयादशमी पर शिवाजी पार्क में संपन्न हुई शिवसेना की विजया दशमी की रैली में बाल ठाकरे ने उनके हाथों में तलवार देकर युवा शाखा की कमान सौंपी. आदित्य ठाकरे मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज के छात्र हैं. मुंबई विद्यापीठ में संपन्न हुये छात्र संघ के चुनाव में उन्होंने शिवसेना को संयुक्त विपक्ष के सामने शानदार कामयाबी दिलाई. बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव और भतीजे राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में खासे चर्चित हैं.

मिलिंद देवड़ा – मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा के पुत्र हैं, जिन्होंने 28 साल की उम्र में 2004 के चुनाव में जीत कर पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया और वर्तमान लोकसभा में वह लगातार दूसरी बार सांसद हैं. राहुल गांधी द्वारा बनाई गई युवा टीम के वह एक तेज़ तर्रार सदस्य हैं. बोस्टन यूनीवर्सिटी से स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने राजनीति को अपने करियर के लिये चुना और उसके लिये उन्हें एक बनी बनाई पृष्ठभूमि तैयार मिली. कांग्रेस के दुर्दिनों में उनके पिता मुरली देवड़ा संकट मोचन के रूप में जाने जाते रहे हैं. उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुये यह भी अपनी स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में मज़बूत कर रहे हैं.

सुप्रिया सुले व अजीत पवार– राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पंवार ने अपनी पुत्री श्रीमती सुप्रिया सुले को 2009 में संपन्न लोकसभा के चुनाव में कराड से लोकसभा का चुनाव लड़ाया, जिसमें जीत हासिल कर उन्होंने लोकसभा में प्रवेश किया. सर्वशिक्षा अभियान को लेकर जनजागृति अभियान चलाने वाली एवं सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली सुप्रिया सुले को सांसद बनाकर उन्होंने यह संदेश तो दे ही दिया है कि उनके राजनीतिक अवकाश के बाद वही है जो उनकी राजनीतिक कमान को संभालेंगी. वैसे उन्होंने अपने भतीजे अजीत दादा पंवार को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनाकर शायद यहीं संकेत दिया है कि दिल्ली में उनकी विरासत उनकी पुत्री सुप्रिया सुले व महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार संभालेंगे.

पंकज भुजबल व समीर भुजबल– महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग की राजनीति में सशक्त चेहरे के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले कबीना मंत्री छगन भुजबल के पुत्र ने जहां राजनीति में विरासत को आगे बढ़ाते हुये नादगांव विधानसभा क्षेत्र से 2009 में चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया. वहीं उनके भतीजे समीर भुजबल ने नासिक लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी का शुभारंभ किया. यह दोनों भाई छगन भुजबल की राजनीतिक ज़मीन को सींचकर और मज़बूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं.

नितेश राणे– अमेरिका से मैनेजमेंट की शिक्षा लेने के बाद नितेश राणे 2005 में वापस आये जब उनके पिता नारायण राणे शिवसेना को गुडबाय कह चुके थे. सामाजिक संगठन स्वाभिमान का गठन कर उन्होंने पूरी मजबूती से अपने पिता का साथ दिया. 2009 के आम चुनाव में रत्नागिरी से लोकसभा के लिये चुने गये. नौजवान नितेश ने अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में नवयुवकों को अपने साथ जोड़ने का काम किया. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे को यह लगता है कि वह युवकों का एक सामानान्तर संगठन बना रहे हैं. उन्होंने इसके लिये नितेश राणे को युवक कांग्रेस में पद लेकर काम करने को कहा मगर उन्होंने इसे नहीं माना और आज उनके संगठन में शामिल नौजवानों की संख्या लाखों की तादाद में है. जो उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. इनके पिता नारायण राणे ने कोकण में अपना प्रभुत्व स्थापित किया. इसे ही अंगीकार कर वह स्वयं को मज़बूत कर रहे हैं

पूनम महाजन– भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में आधार स्तंभ रहे पार्टी के दिग्गज नेता स्व. प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन ने 2006 में अपने पिता की हत्या के बाद राजनीति में आने का फ़ैसला किया. 2009 में संपन्न हुये विधानसभा चुनाव में उन्होंने घाटकोपर की सीट से चुनाव लड़ा. मगर उनको अपने पहले चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा. इस समय पूनम महाजन भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अपनी पार्टी के लिये काम कर रही हैं.

देवेंद्र फडणवीस– नागपुर में भाजपा के कद्दावर नेता और विधायक देवेंद्र फडणवीस को राजनीतिक विरासत पिता गंगाधर फडणवीस से मिली. पाक–साफ़ छवि और व्यापक जनाधार वाले देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान प्राप्त है. काम में स्फूर्ति और सादगीपूर्ण जीवन इनकी युवा सोच का दर्पण है.

सागर मेघे– विदर्भ के कद्दावर नेता सांसद दत्ता मेघे के पुत्र सागर मेघे भी अपने पिता की तरह ही कर्तव्य पारायण हैं. दत्ता मेघे के कार्यकर्ताओं को इनका भी मार्गदर्शन मिलता है. विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं. वह मेघे द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं का कामकाज संभालते हैं.

राजेंद्र मुलक– महाराष्ट्र की राजनीति में भाऊसाहब मुलक का नाम सम्मान से लिया जाता है. भाऊसाहब के पुत्र राजेंद्र मुलक फ़िलहाल महाराष्ट्र के राज्य मंत्री हैं. विधानसभा में चमकते युवा चेहरों में उनकी अलग ख़ासियत है. भाऊसाहब अर्से तक कांग्रेस के नेता रहे. अब राजेंद्र मुलक कांग्रेस की बागडोर अपने क्षेत्र में संभाल रहे हैं.

रणजीत कांबले– वर्धा के निवासी और विधायक रणजीत कांबले को राजनीतिक विरासत प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार की करीबी स्व. प्रभा राव से मिली. प्रभा राव की शख़्सियत से सभी बख़ूबी वाक़िफ़ हैं. कांबले प्रभा राव के भांजे हैं.

वर्षा गायकवाड़– सांसद एकनाथ गायकवाड़ की बेटी वर्षा गायकवाड़ राज्य में महिला और बालविकास मंत्री हैं. वे हिंगोली विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आई हैं. कैबिनेट मंत्री बनने के पहले वह उच्च और तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री के रूप में कामकाज संभाल चुकी हैं. उन्हें राज्य मंत्री से उन्नत कर कैबिनेट में लाया गया.

सुनील केदार– नागपुर में सहकार महर्षि के नाम से मशहूर बाबासाहब केदार के पुत्र सुनील केदार भी व्यापक जनाधार वाले नेता हैं. कार्यकर्ताओं के बीच इनकी अच्छी पकड़ है. इस कारण बिना किसी पार्टी के लेबल के यह निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं. फ़िलहाल विधायक हैं.

प्रणीति शिंदे– केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की पुत्री प्रणीति शिंदे विधायक हैं और अपने पिता की विरासत संभालने के लिए तैयार हैं. नागपुर में विधानसभा सत्र के दौरान जब पहली बार उन्हें विधान भवन परिसर में देखा गया तो मीडिया के लिए वे कौतूहल बन गईं थीं. बाद में लोगों को पता चला कि ये प्रणीति शिंदे हैं.

राहुल बोंद्रे– बुलढाणा ज़िले के चिखली निवासी और विधायक राहुल बोंद्रे ने भी अपने पिता सिद्धविनायक बोंद्रे की विरासत को आगे बढ़ाया है. इनके पिता चिखली नगर परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे. और कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके हैं.

राजेंद्र शिंगणे– राजेंद्र शिंगणे फ़िलहाल विधायक हैं और उन्हें राजनीतिक विरासत अपने पिता भास्कर राव शिंगणे से मिली. भास्करराव मंत्री भी रह चुके हैं.

शेखर शेंडे– वर्धा नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके शेखर शेंडे के पिता प्रमोद शेंडे कांग्रेस के पुराने नेताओं में से एक हैं. विधानसभा के 10 साल तक उपाध्यक्ष रह चुके हैं. 7 बार विधायक बनने वाले प्रमोद शेंडे को महाराष्ट्र की राजनीति में सम्मान की नज़रों से देखा जाता है.

पंकजा पालवे मुंडे– भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गोपीनाथ मुंडे की बड़ी पुत्री पंकजा ने इस बार परली लोकसभा चुनाव क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और बाजी मार ली. वंशवाद को लेकर गोपीनाथ मुंडे को भी लपेटने की कोशिश की गई, मगर जनता ने अपना फ़ैसला सुना दिया. एमबीए तक पढ़ीं पंकजा पुणे में एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती हैं और गोपीनाथ मुंडे की चीनी मिल का सारा कारोबार संभालती हैं. परली निर्वाचन क्षेत्र में पंकजा हर किसी को जानती हैं, जो कभी उनके पिता का क्षेत्र रहा है.

डॉ. मधुसूदन केंद्रे– गोपीनाथ मुंडे के बड़े भाई पंडितन्ना के दामाद डॉ. मधुसूदन परभणी के गंगाखेड़ क्षेत्र से अगली पीढ़ी का प्रतिनिधितत्व कर रहे हैं. वह इससे पहले नगरपरिषद के प्रमुख भी रह चुके हैं.

राजेंद्र शेखावत– राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बेटे राजेन्द्र शेखावत कांग्रेस के टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़े और निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय सुनील देशमुख को हराया. इस चुनाव में देश भर की नज़र थी. वह राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के परिवार द्वारा संचालित विद्याभारती शिक्षण प्रसारक मंडल का प्रमुख के रूप में भी देखरेख कर रहे हैं.

अमित देशमुख – पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के पुत्र अमित देशमुख अमित भैया ने लातूर सीट से बाज़ी मार राजनीतिक गलियारे में दस्तक दी है. अपने पिता विलासराव देशमुख के मुख्यमंत्री रहने के दौरान अमित उनकी आवाज बनकर रहे. वह अपने पिता की शुगर मिल का कामकाज संभालते हैं. माना जाता है कि प्रशासकीय अधिकारियों के बीच उनकी मज़बूत पकड़ है. औपचारिक रूप से वह अपने पिता के राजनीतिक उत्तराधिकारी ही हैं.

ओमराजे निंबालकर – कांग्रेस नेता स्व. पवनराजे निंबालकर के पुत्र ओमराजे निंबालकर उस्मानाबाद से अपने संबंधी और पूर्व राज्यमंत्री राणा जगजीत सिंह पाटिल को हराकर विधानसभा में आए हैं. अपने पिता पवनराजे की हत्या के बाद से तेरना शुगर को–ऑपरेटिव की उन्होंने कमान संभाली है.

सुनील राउत – शिवसेना नेता और राज्यसभा से सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत ने भांडुप क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन वे जीत नहीं सके. मुंबई में आईबीएन–लोकमत समाचार चैनल के दफ्तर पर हमले के बाद सुनील राऊत चर्चा में आए. उनके समर्थकों की मानें तो वे शिवसेना में बीस साल से ज़्यादा समय से कार्यकर्ता की हैसियत से सक्रिय हैं.

संदीप नाईक – राज्य के आबकारी और ग़ैरपरंपरागत ऊर्जा मंत्री गणेश नाईक के बेटे संदीप नाईक मुंबई के पास की ऐरोली सीट से राकांपा के टिकट पर मैदान में उतरे और जीत हासिल की. इसके साथ ही वह भी राज्य की राजनीति में स्थापित हो गए. वह इसके पूर्व नवी मुंबई महानगर पालिका में स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं. उनके भाई संजीव पहले से ही नवी मुंबई के सांसद हैं.

मकरंद जाधव पाटिल – सतारा से राकां के पूर्व सांसद लक्ष्मणराव जाधव पाटिल के पुत्र मकरंद जाधव पाटिल ने सतारा में वाई क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा. फिर भी वह राजनीति में अब पूरी तरह सक्रिय हैं और पिता की विरासत संभालने को तैयार हैं.

feedback@chauthiduniya.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बदहाल है

ठेकेदारों की मिलीभगत

करोड़ों रुपयों की बंदरबांट

नितिन राउत

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्धा ज़िले की सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं. एक ऐसे बड़े घपले को अंजाम दिया गया है, जिसकी दुर्गंध देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है. लेकिन सरकारी तंत्र काली कमाई करने में इतना व्यस्त है कि उसे इस भ्रष्टाचार से कोई लेना–देना नहीं है. इस मामले के दो आश्चर्यजनक पहलू हैं. पहला यह कि कि कांग्रेस के राज में हुए इस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ शिकायत करने वाले सांसद स्वयं कांग्रेसी हैं और दूसरा यह कि सरकारी खेमे की अंदरूनी खींचतान के बीच यह मामला अनदेखा कर दिया गया.

वर्धा ज़िले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2006 से 2010 तक बनाई गईं कई सड़कें अपने स्थान से ग़ायब हैं. दूसरे शब्दों में ये सड़कें काग़ज़ों पर ही बनाई गई हैं. सही में यहां पर कोई काम हुआ ही नहीं है या हुआ भी है तो न के बराबर केवल दिखाने के लिए. ऐसे में जो सड़कें बनाई गईं, वे इतनी घटिया दर्जे की हैं कि छह माह के भीतर ही उखड़कर नष्ट हो गईं. सूत्र बताते हैं कि योजना के अंतर्गत जो निरीक्षण किया गया है, उसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है. वायगांव से अलोडा तक 6 किमी लंबी सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया है. गुंजखडा से सातफल तक का 10 किमी. लंबा रास्ता उखड़ चुका है. मिपरी से लोणी तक के 4 किमी के रास्ते पर काम चालू है, साथ ही उखड़ता भी जा रहा है. हाईवे से आजगांव तक का 1.2 किमी लंबा रास्ता ठीक नहीं बनाया गया है. पुलगांव से कवठा झोपड़ी तक और जामणी देवली से दिघी बोपापुर तक का 12 किमी लंबा रास्ता अपने स्थान पर है ही नहीं. ओआरडी से आपटी तक 1.7 किमी. लंबा रास्ता केवल औपचारिकता निभाने के लिए बनाया गया है. यह संतोषजनक नहीं है. केलापुर से सोनेगांव आबाजी तक का रास्ता बनने के 15 दिन बाद ही उखड़कर इधर–उधर बिखर गया है. सिंधी मेघे से सेलसुरा तक का रास्ता उखड़ चुका है. नियमानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य जानकारियां, योजना, निमार्ण कार्य, लागत आदि दर्शाने वाले बोर्ड कहीं नहीं दिखाई देते हैं. यह ब्यौरा पूरा नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर हुए घपले का छोटा सा उदाहरण भर है. यह भ्रष्टाचार देखकर कोई भी आम आदमी बौखला सकता है तो फिर कांग्रेस के सांसद क्यों नहीं जागते. सांसद दुा मेघे को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में हुए इस भ्रष्टाचार को देखकर रहा नहीं गया. फिर यह मामला दिल्ली पहुंचते देर न लगी. उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों में लगभग 50 करोड़ के घपले का मामला संसद में बजट सत्र के दौरान उठाया. इसके पहले मेघे ने पत्रकारों और अधिकारियों की एक टीम के साथ इस योजना के अंतर्गत बनी सड़कों का मुयायना कर एक रिपोर्ट तैयार की और संसद के पटल पर पेश किया. हालांकि, ज़िला स्तर पर इस योजना के सबसे बड़े अधिकारी कार्यकारी अभियंता तेलरांधे ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वे इस मामले को लेकर किसी भी स्तर की जांच के लिए तैयार हैं. ग़ौरतलब है कि तेलरांधे भी मेघे की उस टीम के सदस्य थे, जिसने सड़कों का मुआयना किया था. तेलरांधे कहते हैं कि उन्हें बुलाया गया और इसलिए वह शामिल हुए. एक तथ्य यह भी है कि इन सड़कों के लिए सारे भुगतान केंद्रीय स्तर की गुणवत्ता परीक्षण समिति की सिफ़ारिशों के बाद ही होते हैं.

भ्रष्टाचार की कहानी इस मोड़ पर आकर कुछ दिनों पहले प्रदर्शित हुई फिल्म वेल डन अब्बा से मिलती–जुलती है, जिसमें एक बावड़ी बनती है. इंजीनियर से लेकर गुणवत्ता परीक्षण अधिकारी तक बावड़ी बनाए जाने और उसके मीठे पानी की रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, सारे बिल पास हो गए, भुगतान की राशि आपस में बांट ली जाती है. पर हक़ीक़त में बावड़ी खोदी ही नहीं गई, काग़ज़ पर सब हो गया. जब परेशान हाल किरदार ने बावड़ी चोरी की रपट सारे काग़ज़ातों के साथ थाने में दर्ज करवाई तो अधिकारी से लेकर मंत्री तक की नींद उड़ी. यहां तो अधिकारी बेख़ौफ़ जांच की मांग कर रहा है. सड़कें यदि बनीं तो गई कहां? इतनी जल्दी टूट–फूट कैसे हो गई? नियमतः पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गई? भुगतान कैसे हो गए? इन सब के लिए एक ही जवाब है, गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट. यह सब एक ऐसे राज्य की हक़ीक़त है, जहां किसान आत्महत्या पर नियंत्रण एक चुनौती बनी हुई है, जहां प्रधानमंत्री योजाना की स्कीमें इसी तरह खाई जा रही हैं, जहां किसानों के लिए आवंटित रकम को मिल बांट कर खाने के आरोप में 405 अधिकारियों पर जांच बैठती है और निलंबन होता है मात्र 50 का. इस जांच और निलंबन के खेल पर भी एक जांच करवा लेनी चाहिए. इस सब के बीच राज्य और केंद्र में सत्ता धारी पार्टी (कांग्रेस) का एक सांसद इस बंदरवाट पर सवाल खड़े करता है और उसकी आवाज़ भी बाबुओं की कार्यप्रणाली का शिकार हो जाती है. सत्ता के इस खेल में कांग्रेस का एक सांसद यदि इतना निरीह है तो आम आदमी का क्या, मरते किसानों का क्या? मेघे ने प्रधानमंत्री के समक्ष कुछ सप्ताह पहले ही महाराष्ट्र के कांग्रेसी सांसदों से उनकी औपचारिक मुलाकात के समय यह सवाल उठाया था. थोड़ी हलचल हुई, फाइलें खुलीं और फिर सब कुछ रुटीन में तब्दील हो गया. कहीं से तो वरदहस्त है तभी तो कार्यकारी अभियंता संसद के सवालों से बेख़ौफ़ सूचित करते हैं. तेलरांधे का कहना है, प्रधानमंत्री के समक्ष जब सवाल उठा तो मुख्य अभियंता के स्तर से जांच हुई. हमारे जवाबों से वे संतुष्ट हो गए. हमने मेघे साहब को भी लिखित तौर पर आमंत्रित किया था कि आकर वे सारी फाइलें देख जायें, वे नहीं आए. हम हर जांच के लिए तैयार हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष जिन तीन सड़कों का मामला उठाया था, उनमें से एक ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आती हैं. शेष पीडब्ल्यूडी के रास्ते हैं. पूरी बातचीत में तेलरांधे ठेकेदारों के बचाव में दलीलें देते हैं. लेकिन हक़ीक़तें दलीलों से नहीं बनती. सड़कों के निर्माण में घोटाला है, यह दत्ता मेघे की रपट से जितना सत्य है, उतना ही इस रिपोर्टर की आखों से भी. तेलरांधे का जवाब राज्य की एक दूसरी मशीनरी को भी लपेट में ले रहा है. सूत्रों के अनुसार एक आदिवासी स्कूल का ठेका अपने मनोनुकूल निर्माण कंपनी को दिलवाने के लिए ज़िला परिषद के अर्धनिर्मित भवन के पूर्ण निर्माण का प्रमाण पत्र दे डाला. इस कंपनी का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में भी एकाधिकार बताया जाता है. लेकिन सवाल यह है कि दत्ता मेघे की पहल असर क्यों नहीं पैदा कर पा रही है. इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक वैमनस्यता आड़े आ रही है. दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में शामिल ठेकेदारों को राज्य के एक प्रभावशाली नेता के खेमे से माना जाता है और कांग्रेस की आपसी खींचतान राज्य की कांग्रेसी राजनीति का लंबा अफ़साना बन चुकी है, जिसकी धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ती है. बताते हैं कि यही कारण है कि मेघे की पहल दिल्ली और मुंबई के गलियारों में आपसी वैमनस्यता के खाते में डाल दी जाती हैं.

वर्धा

feedback@chauthiduniya.com

SMS INFRASTRUCTURE LIMITED
[FORMERLY SHAKTIKUMAR M. SANCHETI LIMITED]
(A Civil Engineering & Infrastructure Development Company)
267, FADNAVIS BHAVAN,
NEAR TRIANGULAR PARK, DHARAMPETH,
NAGPUR 440 010 (M.S.)
Tel 2551952,53,2561904, 5, 6 Fax - (0712) - 2544039
E-mail: sanbros_ngp@sancharnet.in
Website www.smsl.co.in

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 18 अप्रैल-24 अप्रैल 2011

www.chauthiduniya.com

"संजीवनी का है ऐलान,
झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

Website : sanjeevanibuildcon.in

PLOT

BUNGALOW

DUPLEX

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9973959681
9471356199
9431190351
9472727767
9471527830

जनता के मारे ये बेचारे

सालों से सत्ता पर क़ाबिज़ नेताओं पर पिछले विधानसभा चुनाव में जनता का डंडा ऐसा चला कि बिहार के कई चमकदार सियासी चेहरों पर स्याही पुत गई. सत्ता का स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा होने का मुगालता पालने वाले सियासी शूरमा सिमट कर हाशिये पर चले गए हैं. अब कुर्सी की दूरी का ग़म उन्हें सता रहा है.

सरोज सिंह

आचार्य शिवपूजन सहाय ने अमीरी की क़ब्र पर पनपी हुई ग़रीबी को बहुत ज़हरीली माना था. लेकिन, सियासतदानों के लिए इससे भी तीखा ज़हर होता है चुनाव हार जाना. तभी तो कहा गया है कि राजनेता पुत्र शोक सह सकते हैं, कुर्सी खोने का शोक नहीं. कुर्सी के साथ ही पॉवर और ग्लैमर, उनका रौब-रुतबा, ठाठ-बाट जुड़ा हुआ रहता है. पर, बेरहम वक़्त की जद में आने के बाद इन शूरवीरों के भी सुर ताल बिगड़ जाते हैं. यह तो किसी को बख्शता नहीं है. इसी काल की चाल के चक्रव्यूह में फंसकर बिहार के कई चमकदार सियासी चेहरों पर स्याही पुत गई. सत्ता का स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा होने का मुगालता पालने वाले सियासी शूरमा सिमट कर हाशिये पर चले गये हैं. अब भी हाशिये पर से ही हस्तक्षेप की छटपटाहट उन्हें बेचैन किए रहती है. पूर्व मुख्यमंत्री दंपति लालू प्रसाद और राबड़ी देवी इस श्रेणी की अग्रणी शख्सियत हैं. लालू प्रसाद चुनाव हार का संताप मिटाने तीर्थ स्थलों के दौरों में तल्लीन दिखे, वहीं उनकी घरवाली अपनी पुरानी भूमिका में वापस आ गई हैं. दो दशक तक सत्ता का अनवरत आनंद उठाने के बाद इससे महरूम होना उन्हें पच नहीं रहा है. लिहाज़ा राजनीतिक रणनीति और सड़क पर संघर्ष के माद्दे का घोर अभाव लालू प्रसाद के कुनबे में दिखता है. भाग्य और चमत्कार के भरोसे नैया पार लगने का भरोसा पालने की सोच उनके मंदिरों और मजारों की खाक छानने की कवायद से उजागर हो गई है. क़ाबिलेग़ौर है कि लालू प्रसाद अपने सत्तारोहण के प्रथम कार्यकाल में ब्राह्मणवाद के ख़िलाफ़ आग उगलते थे. पोथी-पतरा जलाने की बात करने वाले लालू प्रसाद पर वक़्त की ऐसी मार पड़ी कि उन्हें सुनहरे दिनों की वापसी के लिए उसी द्विजवाद की चौखट पर नाक रगड़ना पड़ रहा है. उनके गठबंधन के सहयोगी लोजपा सुप्रीमो और पार्टी नेताओं के बड़े साहब रामविलास पासवान तो चुनावी पराजय से सबक लेने के बजाए दिल्ली में दिल लगा रहे हैं. बिहार आना भी उन्हें गंवारा नहीं. कुछेक मौक़ों पर अवश्य उन्होंने बमुश्किल उपस्थिति दर्ज करवाई है. इनके अनुज एवं लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस 1977 से गृह विधानसभा क्षेत्र अलौली के आला नेता बने हुए थे. पार्टी में छोटे साहब के रूप में ख्यात पारस का गुरूर टूट गया. गत विधानसभा चुनाव में जदयू के गुमनाम उम्मीदवार रामवृक्ष सदा ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया. उसके बाद उनके दरबार की रौनक ही ख़त्म हो गई. अब तो इनके चरण छूने वालों का भी टोटा हो गया है. पहले उनके चरणस्पर्श कर अहलादित होने वाले राजनीतिक दिग्गजों का तांता लगा रहता था. वैसे कई दिग्गज भाजपा जदयू की पंक्ति में बैठ उनकी खिल्ली उड़ाते नज़र आते हैं. उस दौर में उनके मोबाइल पर घंटी बजती रहती थी. और उन्हें मोबाइल उठा बातचीत करना गंवारा नहीं था. अब तो हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे से भी बात कर लेते हैं. एक और भाई पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के ननिहाल वालों ने ही उनकी खटिया खड़ी कर दी. रिश्ते में ममेरे भाई महेश्वर हजारी ने लोकसभा चुनाव में हेकड़ी गुम कर दी. महेश्वर हजारी उन्हीं के सानिध्य में पहली वार वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से पिता रामसेवक हजारी को दरकिनार कर विधायक बने थे. कहा जाता है कि बाप की टांग खींचने वाला अपनी आदत से बाज नहीं आया. लिहाजा राजनीति की दुकान चलाने के लिए गत विधानसभा चुनाव में कुशेश्वरस्थान से भाग्य आजमाने को मजबूर हुए. वहां भी ननिहाल के ही शशिभूषण हजारी ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया. राजसी शौक पालने वाले रामचंद्र पासवान की भी दिल्ली में गुजर बसर हो रही है. सारण प्रमंडल में सुशासन के क्षत्रप रहे प्रभुनाथ सिंह के प्रभुत्व पर फिलहाल पूर्ण विराम लगा दिया नीतीश कुमार ने. जिस पट्य शिष्य सीवान सांसद ओमप्रकाश यादव के लिए बागावत का दामन थामा था. अब फिर उन्हें बिहार में विकास दिखने लगा है. पहले, ओमप्रकाश यादव प्रभुनाथ सिंह के साथ मिलकर बिहार में ईंट से ईंट बजाने का दावा करते थे. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जमकर इस्तेमाल किया. शार्गिदों को टिकट दिलवाकर अपना उल्लू सीधा किया, फिर रंग बदल नीतीश शरणापन्न हो गये हैं. उधर, उनके बड़बोले उस्ताद प्रभुनाथ सिंह के होश गुम हो गये हैं. उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है. नये दल राजद में भी वह निष्क्रिय हैं. चेले का चोला परिवर्तन उन्हें आश्चर्यचकित करने वाला है. सीवान लोकसभा सीट के चुनाव को प्रभुनाथ सिंह ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था. नीतीश कुमार के इशारे पर ओमप्रकाश यादव के दावे को दरकिनार राज्य सरकार में मंत्री वृष्ण पटेल को वहां से पार्टी उम्मीदवार बनाया गया था. प्रभुनाथ सिंह के समर्थन के भरोसे बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ओमप्रकाश यादव चुनाव जीत सांसद बन गये. जबकि मंत्री वृष्ण पटेल की जमानत जब्त हो गई. यही रार का कारण बना. दुर्भाग्य से उस चुनाव में प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज से हार गये थे. लिहाजा उन्हें पार्टी से किनारा करना आसान हो गया. उनके राजद में जाने के बाद क्षेत्रीय क्षत्रप का जदयू में अभाव हो गया था. इस नीयत से भी कांग्रेसी दिग्गज महाचंद्र प्रसाद सिंह को पार्टी में लाया गया है. वहीं एक अन्य प्रतिद्वंद्वी पूर्व विधायक तारकेश्वर प्रसाद को भी उनकी काट के लिए जदयू का जामा पहनाया जा सकता है. एक और शार्गिद रह चुके सलीम परवेज को विधान परिषद का उपसभापति बनाकर उस्ताद का क़द बौना कर दिया गया. चर्चाओं पर भरोसा करें तो प्रभुनाथ सिंह अपना जलवा कायम रखने के लिए सत्ताधारी जमात में प्रवेश की गुंजाइश बिठा रहे हैं. उनकी नज़र जदयू के बजाय भाजपा पर है. लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी और जनार्दन सिंह सिग्रिवाल को इन्होंने गहरी चोट दी था जिसका ज़ख्म अभी भी हरा है. उनके शार्गिद छपरा के पूर्व विधायक रामप्रवेश राय के भी होश गुम हैं. पहले उनकी जुबान और हाथ दोनों चलते थे. अब खुद सरपरस्त की स्थिति अच्छी नहीं है तो उनको हाव-भाव बदलना पड़ा. राज्य सरकार में मंत्री रहे रामनाथ ठाकुर की चुनावी हार के बाद दुर्गति हो गई है. उन्हें जदयू कार्यालय सचिव की भूमिका में ला दिया गया है. वरिष्ठ मंत्री रहे रामनाथ ठाकुर पार्टी कार्यालय में मंत्री के कार्यकर्ता दरबार में मंत्री को सहयोग करेंगे. उन्हें संबंधित आवेदन और काग़ज़ात के रख-रखाव की ज़िम्मेदारी दी गई है. एक अन्य मंत्री अपनी ठसक के लिए मशहूर थे पूर्व परिवहन मंत्री आर.एन. सिंह. लेकिन परबत्ता में मुंह की खाने के बाद जदयू किसान सेल में दिन काट रहे हैं. वैसे भी खेती किसानी में उनका दिल कभी नहीं लगता है. पहले बिजली विभाग में बतौर इंजीनियर उनकी पौ-बारह थी. फिर राजनीति का चस्का लगा. राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर भगवान सिंह कुशवाहा का भी जलवा अफरोज था. लेकिन चुनावी हार के बाद वह गुमशुदा से हो गये हैं. उनको बुरी तरह मात देने वाले जगदीशपुर के विधायक दिनेश सिंह सुर्खियों में रहते हैं. कुशवाहा समुदाय के एक अन्य स्वयंभू नेता नागमणि की तो भारी दुर्गति हुई. उनके दावों की भी पोल पट्टी खुल गई. उनके पैतृक विधानसभा क्षेत्र कुर्था में उनकी पत्नी पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा को मात्र 2200 मत मिले. ख़ुद मोरवा विधानसभा क्षेत्र में जमानत गंवा बैठे. लिहाज़ा उनका बाज़ार भाव काफ़ी गिरा हुआ है. बेचारे बड़बोलेपन की जद में आकर सबकुछ गवां बैठे. स्वयं विधान पार्षद एवं कृषि मंत्री थे. पत्नी विधायक थीं. लोकसभा के टिकट के लिए बगावत पर उतारू हुए. और, खेल खत्म हो गया. दूसरे दलों में भी उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है. जदयू के ही विधान पार्षद रहे रामबदन राय के साथ भी यही हुआ. पार्टी से बग़ावत कर मुंगेर से बतौर राजद प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ गये. विधान पार्षद का रुतबा भी खो बैठे. हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में पत्नी को लोजपा के टिकट पर मटिहानी से चुनाव लड़वाया, जमानत भी नहीं बचा पाये. अब राजनीतिक पुनर्वास के लिए जुगाड़ भिड़ा रहे हैं. गत विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश प्रसाद सिंह राजद छोड़ कांग्रेस में गये. लेकिन चुनाव के बाद किसी भी हलके में नहीं दिखते हैं. राजनीति में बेअसर हो गये हैं. चर्चा है कि पटना एएन कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू कर सकते हैं. वहीं कांग्रेस छोड़ जदयू में वापस जाना डॉ. अरुण कुमार को रास नहीं आया. कुल मिलाकर कहें तो इनके अलावा और भी कई शूरमा हैं, जो जनता की मार से उबर नहीं पा रहे हैं . लेकिन जनतंत्र का तकाजा तो यही है कि ताक़त जनता ही देती है, इसलिए देर सबेर इन नेताओं को भी जनता के दरबार में ही गुहार लगानी होगी ताकि राजनीति में वे अपने आप को प्रासांगिक बना सकें.

feedback@chauthiduniya.com

बौद्ध मठों ने अपने मंदिरों के प्रवेश द्वार बंद रखे, लेकिन अपने गेस्ट हाउस के दरवाज़े खुले रखे और विदेशी श्रद्धालुओं-पर्यटकों की आवाजाही जारी रही.

बग़ैर हस्ताक्षर वाले फॉर्म को पुलिस द्वारा ज़ब्त तो किया गया, लेकिन ऐसे कई मामले हैं, जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है.

एक नज़र

सीमांचल की योजनाओं में धांधली की आशंका

सीमांचल में विकास संबंधी योजनाओं में बैठे विभागीय अधिकारियों की योजनाओं में भूमिका की जांच हो तो कई ऐसी अहम जानकारी हाथ लग सकती है जो लूट खसोट के साथ उनके द्वारा की गई अनियमितता की पोल खोल सकती है. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल दो किशनगंज के 15 योजनाओं में अनियमितता की बात कही जा रही है. मालूम हो कि विगत दिनों पूर्णिया के प्रभारी मंत्री रामाधार सिंह ने पूर्णिया, धमदाहा, बनबनखी पथ में 50 लाख की लागत से बने पी सी सी सड़क के निर्माण में अनियमितता को पकड़ा. इसमें पीसीसी सड़क की ढलाई गुणवत्ताविहीन आठ इंच के बदले चार इंच कराके कार्य करने वाले ऐजेंसी के द्वारा राशि का उठाव कर लिया गया. इसका निर्माण ग्रामीण कार्य प्रमंडल 2 पूर्णिया के द्वारा कराया गया था. इसी तरह से जलालगढ़ में भी इसी विभाग द्वारा पीसीसी सड़क के निर्माण में अनियमितता हुई.

–नीरज कुमार सिंह

भगवतीपुर में बैजू बाबू की प्रतिमा

गरीबों के सच्चे चिंतक थे बैजू बाबू. मधुबनी के बैजू बाबू के बताए गये मार्ग को आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. उक्त बातें रामकृष्ण महाविद्यालय के अवकाशप्राप्त प्रध्यापक स्व. प्रो. बैद्यनाथ गामी उर्फ बैजूबाबू की मूर्ति का अनावरण करने के दौरान कही गईं. उन्होंने कहा कि बैजू बाबू निर्भीक, ईमानदार व्यक्ति थे. बैजू बाबू ने कभी जातिवाद नहीं किया. उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में ग़रीबी भी बढ़ रही है और अमीरी में वृद्धि हो रही है.समारोह का संचालन डॉ. अरूण कुमार मिश्र कर रहे थे वहीं अध्यक्षता राम करण यादव ने की.

–मनीष कुमार झा

पर्यावरण जागरूकता अभियान की खानापूर्ति

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत समस्तीपुर ज़िले में रूरल यूथ को-ऑर्डिनेशन, पटना द्वारा प्रायोजित ज़िले के लगभग 40 स्वंयसेवी संस्थान को पर्यावरण सुरक्षा हेतु कार्यशाला, रैली एवं पौधारोपण का कार्य आयोजित करना है, लेकिन इक्के-दुक्के एनजीओ को छोड़ बांकी पर्यावरण जागरूकता अभियान के लिए केंद्र द्वारा राज्य एवं जिले में भेजी गई राशि की लूट-खसोट हो रही है. शायद ही कोई संस्थान होगा जिसने सही मायनों में पौधारोपण किया हो, क्योंकि पूर्व से ही ज़िले के संस्थानों को कार्यक्रमों के आयोजन की कागजी खानापूर्ति की आदत लगी हुई है और इस बार भी आदतन संस्थानों द्वारा पर्यावरण जागरूकता का आयोजन किया जा रहा है.

–अजय कुमार सिन्हा

महनार में पेयजल के लिए हाहाकार

पीएचईडी की लापरवाही के कारण पूरे वैशाली ज़िला में पेयजल के लिए हाहाकार मचा है. सबसे ज्यादा बुरी स्थिति महनार की है. यहां कनीय अभियन्ता व सहायक अभियन्ता कब आते हैं, किसी को पता नहीं है. आम जनता उनसे भेंट नहीं कर पाती है. क्षेत्र के चमरहरा लावापुर, हसनपुर, मुरौबतपुर,सुल्तानपुर, महनार नगर क्षेत्र इत्यादि स्थानों पर चापाकल खराब पड़े हैं, किन्तु अधिकारियों-कर्मियों को इससे कोई मतलब नहीं है.

–अंजुम परवेज

राजेश अध्यक्ष और ओम प्रकाश सचिव

संताल परगना चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की द्विवार्षिक आमसभा सह चुनाव में सर्वसम्मती से राजेश राजपाल अध्यक्ष एवं ओम प्रकाश छावछरिया महासचिव चुने गए. कोषाध्यक्ष पद के लिए पवन टमकोरिया एवं संयुक्त सचिव प्रेम अग्रवाल एवं आलोक मलिक चुने गए. इससे पूर्व 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव वोट डालकर 44 सदस्यों ने किया, जिसके बाद बैठक कर पदाधिकारियों का चयन किया गया. उपाध्यक्ष पद पर अशोक कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार सुल्तानिया एवं शकर लाल सिंघानिया चुने गए. नव निर्वाचित अध्यक्ष राजेश राजपाल ने कहा कि सर्वप्रथम सभी व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करना मेरी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सदस्यों ने जो ज़िम्मेदारी दी है उसका सही तरीके से निर्वहन करूंगा.

–रणजीत झा, देवघर

उपेंद्र ज़िला पार्षद बनने की तैयारी में

वैशाली ज़िला परिषद क्षेत्र सं. 35 से निवर्तमान ज़िला पार्षद उपेंद्र राय ने पुन: नामांकन कर चुनाव में सनसनी ला दी है. एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में राजनीति का सफर आरंभ करने वाले उपेंद्र राय अपने आपको लालू यादव का आशीर्वाद प्राप्त होने का दावा करते हैं. उन्होंने सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के प्रमुख का पद भी प्राप्त किया एवं 2006 में ज़िला पार्षद बने तथा पुन: ज़िला पार्षद बनने की तैयार में है.

छात्रों ने विद्यालय में ताले जड़े

खगड़िया के हथवन मध्य विद्यालय में बिहार दिवस पर क्रिकेट व कबड्डी प्रतियोगिता न होने पर दर्जनों छात्रों व ग्रामीणों ने स्कूल में ताले लगाकर जमकर हंगामा किया. बिहार दिवस के अवसर पर क्रिकेट व कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. यहां ऐसा न होने की वजह से विद्यालय के दर्जनों छात्र व स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए.

–चौथी दुनिया ब्यूरो

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT

- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
- ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of Patna University & Magadh University get Practical Training.

FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday

Excellent Placement with Handsome Salary

Website : www.psfsm.com

410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-6455019, Mob. : 9334107607, 9835042835, 9234729075

जाली नोट के धंधे का ठिकाना

[illegible]

जयनगर

जाली नोट कारोबार भ्रामक नाम व पते पर चलाया जाता है. जिससे जाली नोट के साथ गिरफ्तारी के बावजूद पूरे नेटवर्क का पता नहीं चलता. जांच एजेंसियों के अनुसार फ़र्ज़ी नाम व पते के कारण नेटवर्क का ख़ुलासा नहीं हो पाता है.

गंडक तबाही मचा सकती है

सुरक्षा को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने बैराज की मरम्मत के लिए 15 करोड़ 80 लाख रुपए आवंटित किए हैं. अगर समय रहते इसकी मरम्मत सही ढंग से नहीं हुई तो इस बार के बरसाती मौसम में यह बैराज गंडक नदी की तेज़ तूफ़ानी धारा का शिकार बन सकता है.

प्रो अरविंद नाथ तिवारी

चंपारण

बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जोड़ने वाला गंडक नदी पर बैराज हाई टेक बनते- बनते स्थानीय सुरक्षा पर सवालिया निशान बनता जा रहा है. गत वर्षों से बैराज के लगभग सभी फाटक जीर्ण शीर्ण होने के कारण बरसात में सुरक्षा को लेकर ख़तरे का कारण बनते नज़र आ रहे हैं. यहां के लोगों को यह शंका है कि कहीं कोसी नदी पर स्थित कुसहा बांध की कहानी फिर बिहार में दोहरायी न जाए. हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने इसकी मरम्मत के लिए 15 करोड़ 80 लाख रुपये का आवंटन दिया है. मरम्मत का कार्य नागार्जुन कम्पनी और कोलकाता की एक कम्पनी ने अपने ज़िम्मे ले रखा है. अगर समय रहते इसकी मरम्मती सही ढंग से नहीं हुई तो इस बार की बरसात में यह बैराज गंडक नदी की तेज़ तूफ़ानी धारा का शिकार बन सकता है. अगर ऐसा हुआ तो बिहार में गंडक नदी कोसी की तरह बर्बादी का कहर चम्पारण, छपरा, सीवान, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश के पडरौना में बरपा सकती है.

गौरतलब है कि बहुत अधिक प्रयास के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने नेपाल के महाराजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव से मैत्री सम्बन्ध स्थापित करके गंडक नदी पर बैराज का निर्माण सन् 1964 ईसवी में कराया था. निर्माण कराने का बहुपक्षीय लाभ निर्धारित था. नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में क्रांति साबित हुई. दोनों देशों के सांस्कृतिक गतिविधि के साथ-साथ आर्थिक संबंध भी मज़बूत हुए. नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती को सींचने के लिए नहरों का जाल बिछाया गया. जहां आज भी तीनों राज्य लाभान्वित हो रहें हैं. इस बैराज के पानी से पश्चिमी नहर के बासठ आरडी पर सूर्यपूर की पन्द्रह मेगावाट बिजली उत्पादन करनेवाली जल विद्युत परियोजना नेपाल में मौजूद है. उत्तर प्रदेश की तरफ हजारों हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होती है. इसके अलावा तिरहुत नहर , दोन नहर भी निकली है .बिहार के मध्य तक लाखों हेक्टेयर भूमि की इससे सिंचाई होती है. पूर्वी नहर स्थित 6 आरडी के नजदीक रमपुरवा में 15 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का संचालन होता है . इसके साथ ही कुछ दूरी पर चार प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है. बैराज के यांत्रिक रख रखाव का कार्य प्रमंडल बाल्मीकि नगर द्वारा किया जाता है. जानकारी के अनुसार यांत्रिक रखरखाव और नहरों की मरम्मत और सफ़ाई के ख़र्च पर बिहार सरकार ने 12 करोड 80 लाख रूपया आवंटन दे रखा है. इसके अलावा बैराज के फाटक मरम्मत पर 3 करोड़ का आवंटन दे रखा है. यांत्रिक रख रखाव और नहरों की मरम्मत और साफ़ सफाई की ज़िम्मेदारी नागार्जुन कंपनी ने ले रखी है. वहीं फाटकों की मरम्मत की जिम्मेदारी कोलकाता की आर बी एन कंपनी ने ले रखी है. स्थानीय लोगों का कहना कि 15 जून के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, फाटक की मरम्मती तभी बढ़िया ढंग से हो सकती है, जब मरम्मत किये जा रहे फाटक के पास पानी का स्त्राव बिल्कुल बन्द किया जाए. जबकि पानी के स्त्राव में फाटक मरम्मती का कार्य किया जा रहा है. इसमें भी स्थानीय अनुभवहीन लोगों से तकनीकी काम लिया जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि पैसे का बंदरबाट हो रहा है. लोगों का मानना है कि ठेके पर काम देने से बैराज की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. आने वाले बरसात के मौसम में अगर बैराज टूटेगा तो बिहार के चम्पारण, गोपालगंज, सीवान , छपरा, उत्तर प्रदेश के पडरौना, कुशीनगर ज़िले तक गंडक नदी कहर बरपा सकती है. हालांकि विभाग के यांत्रिक अभियन्ता ए के शर्मा का कहना है कि काम सही ढंग से किया जा रहा है. विद्युतीय व यांत्रिक ऑटोमाइजेशन करके बिल्कुल हाईटेक किया जायेगा. बैराज पर किसी तरह का ख़तरा आने वाले 20 साल तक मौजूद नहीं रहेगा. लेकिन जिस तरह से काम हो रहा उसे देखकर तो यही लगता है कि कि गंडक कहीं विनाशक रूप न धारण कर ले.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

ज़िला अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न

ज़िला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार मदन कांत ठाकुर एवं पांचवीं बार प्रणय कुमार सिन्हा निर्वाचित हुए. वरीय उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह एवं कोषाध्यक्ष पद पर हलधर प्रसाद सिंह विजयी हुए. नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन कांत ठाकुर ने कहा कि अधिवक्ताओं के हित में हमेशा काम करूंगा. महासचिव प्रणय कुमार सिन्हा ने कहा कि वकीलों की समस्याओं के प्रति हमेशा ही गंभीर रहा हूं तथा आगे भी समस्याओं को दूर करने की दिशा में कार्य करता रहूंगा. इसके अलावा संयुक्त सचिव एवं प्रशासनिक समिति का भी चुनाव किया गया.

–रणजीत झा

टेक्नो मिशन में नामांकन की होड़

समस्तीपुर ज़िले के शिक्षा जगत में क्रांतिकारी कदम बढ़ाते हुए प्रसिद्ध शिक्षाविद् ए के लाल के द्वारा संचालित टेक्नोमिशन स्कूल का प्रथम सेशन गत 04 अप्रैल से प्रारंभ हो गया. इस अवसर पर टेक्नो मिशन प्रबंध समिति के सचिव उदयशंकर सिंह ने कहा कि एक ही कैम्पस में केजी से पीजी स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा मूल उद्देश्य है जिसमें जिले के छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है. स्थानीय समस्तीपुर क्लब के परिसर में संचालित नवोदित टेक्नो मिशन में नामांकन कराने के लिए बच्चों एवं अभिभावकों में होड़ मची है.

अतिक्रमणकारियों की ख़ैर नहीं

समस्तीपुर ज़िला गठन 14 नवम्बर 1972 के बाद अब तक ज़िले में पदस्थापित होने वाले जिलाधिकारियों में से वर्तमान युवा जिलाधिकारी कुंदन कुमार की सर्वत्र सराहना हो रही है क्योंकि कानून के क्रियान्वयन में मानवीय मूल्य एवं नैतिकता को तरजीह देते हुए ज़िलाधिकारी ने बहुत कम समय में ज़िले की 34 लाख आबादी का मन जीतने का काम किया है. ज़िला मुख्यालय की प्रमुख सड़के जो अतिक्रमण की वजह से सिकुड़ती चली जा रही थीं, को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अतिक्रमण मुक्त करा लोगों को राहत दी है. समाहरणालय रोड, ताजपुर रोड, थानेश्वर स्थान मंदिर आदि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने में ज़िलाधिकारी ने अब तक पदस्थापित सभी जिलाधिकारियों को पीछे छोड़ दिया है. स्टेशन रोड उर्फ़ राजेंद्र पथ को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने में प्रशासन हमेशा से अक्षम साबित रहा है. कुंदन कुमार से शहरवासियों को अपेक्षा है कि शीघ्र ही राजेन्द्र पथ एवं मारवाड़ी बाजार को भी अतिक्रमण मुक्त बनाकर आम जनता की सुविधा का ख्याल रखा जाएगा.

–चौथी दुनिया ब्यूरो

विदेशी बौद्ध महाविहारों और बिजली विभाग में ठनी

सुनील सौरभ

भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया स्थित क़रीब 2 दर्जन विदेशी बौद्ध महाविहारों में स्थित मंदिरों के प्रवेश द्वार पर एक पखवाड़े तक ताले जड़ दिए जाने के बाद से बोधगया की राजनीति गर्म हो गई है. विद्युत बोर्ड ने विदेशी बौद्ध महाविहारों पर क़रीब 6 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया हो जाने के बाद विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की तो विदेशी बौद्ध विहारों में एकजुट हों विरोध में अपने-अपने परिसर स्थित मंदिरों में ताले लगा दिये. इन विदेशी बौद्ध महाविहारों की मांग है कि विद्युत कनेक्शन का विपत्र घरेलू दर पर दिया जाए. बोधगया के विदेशी बौद्ध मठों में अत्याधुनिक सुविधायें उपलब्ध हैं. भगवान बुद्ध ने ज्ञान के लिए जिस सुख-वैभव को त्यागा, आज उनके अनुयायी बोधगया के विदेशी बौद्ध मठों में अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के बीच रह रहे हैं. सिर्फ़ कहने के लिए बौद्ध भिक्षु, लामा हैं. विद्युत बोर्ड की कार्रवाई के ख़िलाफ़ विदेशी बौद्ध मठों ने जो आंदोलन छेड़ा, वह स्थानीय लोगों को नागवार गुज़रा, क्योंकि बौद्ध मठों ने अपने मंदिरों के प्रवेश द्वार बन्द रखे, लेकिन अपने गेस्ट हाउस के दरवाजे खुले रखे और विदेशी श्रद्धालुओं-पर्यटकों की आवाजाही जारी रही. अब जब कि विद्युत बोर्ड ने बौद्ध मठों पर बिजली बिल बकाया होने की वजह से 8 बौद्ध मठों का कनेक्शन काट दिया तो विदेशी बौद्ध मठों की संस्था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कांउसिल ने इन मठों को नॉन-डोमेस्टिक सर्विस-3 में रखकर विद्युत विपत्र देने की मांग कर रही है. बोर्ड के नियमानुसार 30 किलोवाट से ज़्यादा खपत होने पर वैसे मठों-संस्थाओं को एनडीएस-2 में रखा जाता है. विद्युत बोर्ड का कहना है कि इन बौद्ध मठों का व्यवसायिक उपयोग किया जाता है और मांग घरेलू विद्युत विपत्र का की जाती है जो कि ग़लत है. सच्चाई तो यह है कि इन विदेशी बौद्ध मठों के गेस्टहाउस का होटल की तरह टेरिफ बना है और श्रद्धालुओं-पर्यटकों को ठहरा कर होटल की तरह राशि वसूली जाती है. विद्युत बोर्ड का कहना है कि महाबोधि मंदिर का रकबा बहुत बड़ा है, बावजूद इसके प्रतिमाह मात्र 24 किलोवाट का बिजली बिल आता है. जबकि विदेशी बौद्ध मठ इससे दो गुना ज़्यादा विद्युत खपत करते हैं. जिन बौद्ध मठों के विद्युत कनेक्शन बकाया रहने पर काटे गये थे. इनमें जापानी इंटरनेशनल रेस्टहाउस (11 लाख), इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर (2.40 लाख), थाई मोनास्ट्री (10.32 लाख), तिब्बतियन धर्मशाला (2.31 लाख), एसआरसी ट्रस्ट टेंपल (2.59 लाख), ताईबान टेंपल (9.1 लाख) शामिल है. हालांकि एक पखवाड़े बाद ज़िला प्रशासन की पहल पर विदेशी बौद्ध मठों ने अपने मंदिर के प्रवेश द्वार के ताले को हटाया. इस दौरान इन मठों के गेस्टहाउस के दरवाज़े खुले रहे. इसी से इनकी नीयत को समझा जा सकता है. इस मामले को लेकर बोधगया में राजनीति शुरू हो गई है. लोजपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक कुमार सर्वजीत ने विदेशी बौद्ध मठों की मांग को जायज़ बताते हुए बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के गेस्टहाउस से भी व्यवसायिक दर पर बिजली बिल वसूलने की मांग विद्युत बोर्ड से की. बोधगया मंदिर प्रबंध समिति के पूर्व सचिव डॉक्टर कालीचरण सिंह यादव ने भी विदेशी बौद्ध मठों की मांग को जायज़ बताया है. वहीं दूसरी ओर बोधगया होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जय सिंह और सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा है कि विद्युत बोर्ड की कार्रवाई सही है. विदेशी बौद्ध मठों ने बोधगया के होटल व्यवसाय को चौपट कर दिया है. इन दोनों ने कहा कि व्यवसाय करने वाले बौद्ध महाविहारों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध एसोसिएशन पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा करेगा. ये विदेशी बौद्ध मठ अपने गेस्टहाउस का व्यवसयिक उपयोग करते हैं और घरेलू विद्युत विपत्र देना चाहते हैं. यह ग़लत है. बोधगया नगर पंचायत की अध्यक्ष प्रीत सिंह ने भी विदेशी बौद्ध मठों पर विद्युत बिल का लाखों रुपया बकाया हो जाने पर विद्युत कनेक्शन काटे जाने को सही कहा है. जबकि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कांउसिल के अध्यक्ष तेनजिन लामा ने बताया कि पहले इन मठों को घरेलू दर पर बिजली बिल भेजा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से व्यवसायिक दर से बिल भेजा जा रहा है. इसी कारण बौद्ध मठों ने बिजली बिल का भुगतान बंद कर दिया है. इस मामले पर विदेशी बौद्ध मठों के मंदिर में ताले लगा दिये जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 18 मार्च को जब महाबोधि मंदिर में प्रार्थना सभा में भाग लेने आए तो नाखुश दिखे, क्योंकि विदेशी बौद्ध मठों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से अपनी बात कहने के लिये प्रयास करते रहे लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई तरजीह नहीं दी. इसी के बाद से विदेशी बौद्ध मठों का मनोबल कुछ टूटा और अंतत: ज़िला प्रशासन की पहल पर विदेशी बौद्ध मठों ने अपने-अपने मंदिर में लगे प्रवेश द्वार के ताले को खोला. विद्युत बोर्ड के सूत्रों के अनुसार बोधगया में 22 ऐसे विदेशी बौद्ध मठ हैं, जिन पर 30 किलोवाट से अधिक का लोड है. विद्युत दर निर्धारण पर बिजली बोर्ड के पदाधिकारियों का कहना है कि इसका निर्धारण पावर रेग्युलिटरी कमिशन के द्वारा किया जाता है. बौद्ध मठों को नॉन-डोमेस्टिक सर्विस 3 के लिये वहां आवेदन देकर गुहार लगानी चाहिए. वास्तविकता यह है कि बोधगया स्थित विदेशी बौद्ध मठ अत्याधुनिक सुख-सुविधा के संसाधनों से युक्त है और स्टार होटलों की तरह पर्यटकों, श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध कराता है. इन मठों की संस्था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कांउसिल भी सिर्फ़ यहां के विदेशी बौद्ध मठों को सुरक्षा कवच के रूप में काम आती है.

इस मामले को लेकर बोधगया में राजनीति शुरू हो गई है. लोजपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक कुमार सर्वजीत ने विदेशी बौद्ध मठों की मांग को जायज़ बताते हुए बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के गेस्ट हाउस से भी व्यवसायिक दर पर बिजली बिल वसूलने की मांग विद्युत बोर्ड से की.

feedback@chauthiduniya.com

फ़र्ज़ी काग़ज़ात पर बिक रहे हैं सिम कार्ड

कई बार जेल के अंदर से भी मोबाइल और सिम बरामद हुए. मामला सुर्ख़ियों में आया, बावजूद इसके पुलिस यह जांच नहीं कर सकी कि आख़िर जेल में बंद मुजरिम के पास से जो मोबाइल या सिम बरामद हुए, आख़िर किसके नाम से निर्गत है. पुलिस की दरियादिली का ही नतीजा हैं कि नक्सलियों तक भी फ़र्ज़ी वोटरकार्ड के आधार पर निर्गत सिम पहुंच रहे हैं.

राजेश सिन्हा

खगड़िया ज़िले में फ़र्ज़ी पहचान पत्र के आधार पर विभिन्न कंपनियों के सिम धड़ल्ले से बिक रहे हैं. शातिर दिमाग़ी लोग फ़र्ज़ी पहचान पत्र के आधार पर निर्गत सिम के ज़रिए कई तरह के अपराध को अंजाम भी दे रहे हैं. मामला सामने आने पर पुलिस मुस्तैदी दिखाती है, लेकिन मामला ठंडा होते ही पुलिस सुस्त हो जाती है. कई बार जेल के अंदर से भी मोबाइल और सिम बरामद हुए. मामला सुर्ख़ियों में आया, बावजूद इसके पुलिस यह जांच नहीं कर सकी कि आख़िर जेल में बंद मुजरिम के पास से जो मोबाइल या सिम बरामद हुए, आख़िर किसके नाम से निर्गत है. पुलिस की दरियादिली का ही नतीजा है कि नक्सलियों तक भी फ़र्ज़ी वोटरकार्ड के आधार पर निर्गत सिम पहुंच रहे हैं. पुलिस को कई तथ्यों की जानकारी तो पहले से थी लेकिन मामला हाईप्रोफाइल न बन पाने के कारण दफ़न था. इस बात का ख़ुलासा तब हुआ जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, खगड़िया डीएम पलका सहनी, एसपी मिठु प्रसाद तथा ज़िला परिषद अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव के मोबाइल पर दरभंगा ज़िले के लहेरियासराय निवासी रामानंद मंडल के नाम से निर्गत सिम के ज़रिए जान से मारने के धमकी दी गई. मोबाइल पर धमकी मिलने के बाद जब मामले की छानबीन शुरू हुई तो यह प्रमाणित हो गया कि खगड़िया ज़िले में विभिन्न सिम विक्रेता नियम क़ानून को ताक पर रखकर सब्जी की तरह सिम बेच रहे हैं. न ही सिम ख़रीदने वाले उपभोक्ताओं के प्रमाण पत्र पर ग़ौर किया जा रहा है और न ही ख़रीददार से हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं. सिम बेचने की आपाधापी में विभिन्न सिम विक्रेता ख़रीददार को बग़ैर किसी काग़ज़ात के ही सिम उपलब्ध करा रहे हैं. इतना ही नहीं विभिन्न कम्प्यूटर सेंटर से भी फ़र्ज़ी वोटर आईकार्ड बनवाकर शातिर लोग सिम विक्रेता के पास पहुंचते हैं और दुकानदार आंख मूंदकर सिम उपभोक्ता के हाथ में थमा देते हैं. वोटर आईकार्ड किसी का होता है और फोटो किसी और की, लेकिन सिम विक्रेता आपत्ति जताए बग़ैर उपभोक्ता को सिम उपलब्ध करा देते हैं. इस तरह की जानकारी मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने सर्वप्रथम सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य वीआईपी को धमकी देने में प्रयोग किए गए सिम के संदर्भ में पड़ताल की. पुलिस को यह जानकारी मिली कि सुनील कुमार लहेरी ने लहेरियासराय निवासी रामानंद मंडल के नाम से जारी वोटर आईकार्ड के आधार पर खगड़िया ज़िले के एक सिम विक्रेता से सिम की ख़रीददारी की. दुकानदार ने दरियादिली का परिचय देते हुए सुनील से बग़ैर हस्ताक्षर लिए उसे सिम उपलब्ध करा दी. ग़ौर करने वाली बात है कि दुकानदार ने आख़िर किस आधार पर लहेरियासराय निवासी मंडल के वोटरआई कार्ड पर सुनील को सिम उपलब्ध कराई. ख़ैर जिस सिम के ज़रिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य वीआईपी को एसएमएस भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई थी, उस सिम को बेचने वाले दुकानदार की दुकान को पुलिस ने तत्काल सील कर दिया. बग़ैर हस्ताक्षर वाले फॉर्म को पुलिस द्वारा ज़ब्त तो किया गया लेकिन ऐसे कई मामले हैं, जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है. इस ज़िले के विभिन्न दुकानों से निर्गत सिम के संदर्भ में जानकारी हासिल करने पर यह जानकारी मिली कि फ़िलवक़्त बीएसएनएल के 22000, एयरटेल के 1.42 लाख, डोकोमो के 14000, रिलायंस के 22000, यूनिनॉर के 14000, वोडाफोन के 1.30 लाख तथा एसटेल के 8500 सौ उपभोक्ता हैं. पुलिस को यह जांच करने की ज़रूरत है कि इतने उपभोक्ताओं में से कितने लोगों ने सही प्रमाणपत्र तथा कितने लोगों ने फ़र्जी कार्ड पर सिम ख़रीदी है, क्योंकि सुनील ऐसा पहला शातिर नहीं है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के नाम से सिम ख़रीदकर किसी वीआईपी को धमकी दी है. ऐसे कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं. मामले की जांच भी हुई और ऐसी करतूत करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा. कई मामले अब भी लंबित हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान संभव नहीं हो सकी है. पुलिस द्वारा धमकी देने में प्रयोग की [illegible] सिम के संदर्भ में जांच की गई तो यह बात सामने आई कि जि[illegible] नाम से सिम ली गई है, वास्तव में उस नाम का व्यक्ति है ही नहीं. [illegible] सवाल यह उठता है कि पुलिस ऐसे दुकानदारों की नाक में नक[illegible] कसेगी या मोबाइल के द्वारा धमकी देने के मामले सामने आते र[illegible] और पुलिस नाहक परेशान होती रहेगी. कुछ जानकारों से बात क[illegible] पर यह बात सामने आई कि कुछ लोग अपने दुश्मन से बदला [illegible] के लिए भी उसके नाम से फ़र्ज़ी वोटर आईडी बनवाकर सिम [illegible] ख़रीददारी करते हैं और किसी वीआईपी को धमकी देकर अपने दुश्[illegible] को परेशान करने से परहेज नहीं करते हैं. सुनील की ही बात की ज[illegible] तो वह अपने कई दुश्मनों के नाम से सिम ख़रीद चुका था. इसी ब[illegible] उसकी प्रेमिका ललिता ने उसको धोखा दे दिया. नतीजतन उ[illegible] पिता को परेशान करने के लिए उसने प्रेमिका के पिता का वो[illegible] आईडीकार्ड चुराकर उनके नाम से सिम की ख़रीददारी की और उ[illegible] फंसाने के लिए इस तरह का कुचक्र रचा. जानकारों के मुताबि[illegible] अंगिका व भोजपुरी फिल्म बनाने के दौरान लहेरियासराय निवा[illegible] रामानंद मंडल की पुत्री ललिता से उसे प्रेम हो गया. ललिता के प्रे[illegible] में पागल सुनील ने बीते चार वर्षों में उसके पीछे लाखों रुपए पानी की तरह बहाए. मंदिर में जाकर शादी भी रचाई. लेकिन जब ललिता सुनील के साथ बेवफाई पर उतर गई, तब उसे सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा क़दम उठाया. ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसकी जड़ में पुरानी दुश्मनी का मामला सामने आया है. सुनील की गिरफ्तारी के दिन ही पंकज पंडित भी पुलिस द्वारा दबोचा गया. दरअसल इसके नाम से भी निर्गत सिम के जरिए कई वीआईपी को धमकी दी गई थी. पड़ताल में यह बात सामने आई कि उसके भी पहचान पत्र और फोटो का ग़लत उपयोग किया गया है.

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 18 अप्रैल–24 अप्रैल 2011

बिहार का साफ़ तौर से विभाजन हो रहा है और हमारी चिंता का कारण विभाजन से प्रभावित होने वाले झारखंड रहित बिहार का आर्थिक हित है.

विशेष राज्य के दर्जे की मांग और दावा

औचित्य बनाम राजनीति

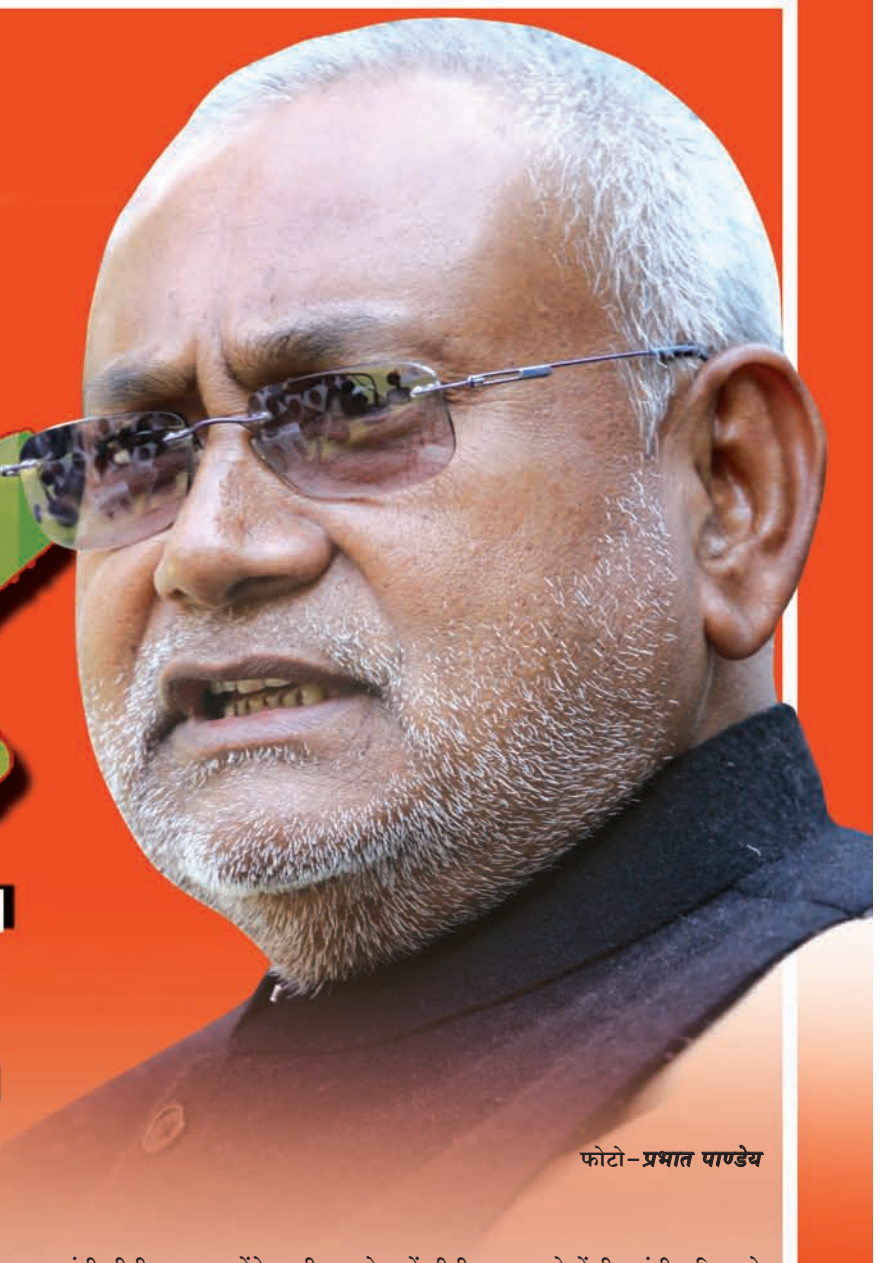

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

पी.के. सिन्हा

इन दिनों बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ज़ोरदार अभियान चला रही है. इस अभियान में कुछ समाचार पत्र एवं पत्रकार पत्रकारिता की मूल भूमिका तथा निष्पक्षता की मर्यादा का परित्याग करते हुए राजनीतिक दलों की तरह सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं. ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसके औचित्य पर प्रश्न खड़ा करने वाले अथवा तथ्यों के आलोक में इसकी सच्चाई का ख़ुलासा करने वाले बिहार विरोधी की श्रेणी में आ जाएं. ऐसी स्थिति में राज्य की जनता की जानकारी के साथ-साथ इस राज्य के हित में प्रासंगिक तथ्यों के आलोक में सच्चाई को जानना तथा पर्दे के पीछे की राजनीति का ख़ुलासा करना अत्यंत प्रासंगिक एवं अत्यावश्यक है.

उपर्युक्त संदर्भ में सर्वप्रथम इस ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट कराना अत्यंत प्रासंगिक है, जो 26 अप्रैल 1998 को तत्कालीन रक्षा मंत्री एवं राजग संयोजक जॉर्ज फर्नांडीस तथा उस समय के रेल मंत्री नीतीश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में समता पार्टी के सभी सांसदों, पार्टी पदाधिकारियों एवं प्रमुख नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया था. उक्त सुविचारित एवं महत्वपूर्ण ज्ञापन का प्रारंभिक एवं अंतिम अनुच्छेद वर्तमान संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक होने के कारण इस तरह से है. प्रशासनिक कुशलता और सम्यक विकास के दृष्टिकोण से छोटे राज्यों की आवश्यकता है, इस बात पर एक तरह से राष्ट्रीय सहमति बन चुकी है. संभवत: इसी नज़रिए से वर्तमान बिहार से दक्षिणी झारखंड इलाक़े को लेकर एक नया राज्य बनाने की प्रक्रिया अथवा चर्चा चल चुकी है. प्रस्तावित राज्य, जिसे राष्ट्रीय एजेंडे में वनांचल के नाम से अभिहीत किया गया है, के बनने से बिहार का साफ़ तौर से विभाजन हो रहा है और हमारी चिंता का कारण विभाजन से प्रभावित होने वाले झारखंड रहित बिहार का आर्थिक हित है. समता पार्टी प्रारंभ से झारखंड राज्य का समर्थन करती रही है और आज जब इसे सचमुच एक अलग राज्य का दर्जा दिया जा रहा है तब हम इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन शेष बिहार के आर्थिक हितों की चिंता करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है. इस ज्ञापन का उद्देश्य झारखंड के अलग होने से बिहार के आर्थिक और वित्तीय स्वरूप पर होने वाले असर और उसकी पूर्ति के लिए एक विशेष पैकेज की मांग करना है. इसके उपरांत ज्ञापन में विभाजन से संबंधित आंकड़ों एवं लाभ-क्षति आदि का विवरण देते हुए अंतिम अनुच्छेद में निम्नांकित मांग की गई थी. अंतिम प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है.

इसलिए समता पार्टी मांग करती है कि झारखंड राज्य अवश्य बने, किंतु इसके बनने से बचे हुए बिहार को जो आर्थिक नुक़सान होने जा रहा है, उसकी संपूर्ति के लिए झारखंड राज्य की घोषणा के साथ ही एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की जाए. इस आर्थिक पैकेज को दो स्तरों पर होना चाहिए. पहले स्तर पर कम से कम 50,000 करोड़ रुपये की एक मुश्त राशि बिहार के समुचित विकास के लिए मिलनी चाहिए, ताकि टाटा, बोकारो, झरिया हटिया जैसे अनेक औद्योगिक क्षेत्रों से रहित बिहार अपनी ज़रूरतों और अनुकूलता के अनुसार एक औद्योगिक विकल्प खड़ा कर सके. इस पैकेज का उपयोग कृषि, सिंचाई, बिजली, सड़क और उद्योगों के विकास पर किया जा सकेगा. उत्तर बिहार और मध्य बिहार में अनेक औद्योगिक प्रक्षेत्र थे, जो एक-एक कर बंद हो गए. डालमिया नगर, बरौनी, कटिहार, फतुहा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को अल्प समय में पुनर्जीवित किया जा सकता है. सिंचाई की सुव्यवस्था और जल प्रबंधन करके मध्य बिहार के बड़े भूभाग की कायापलट की जा सकती है. उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण का समुचित प्रबंध कर वहां की कृषि को पुख्ता आधार दिया जा सकता है. चीनी और जूट उद्योग का आधुनिकीकरण करके वहां रोज़गार के अकूत अवसर पैदा किए जा सकते हैं. दूसरे स्तर पर कम से कम दस वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपये की राशि बिहार को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलनी चाहिए, ताकि अपना एक स्वावलंबी ढांचा विकसित होने तक बिहार अचानक हुए अपने राजस्व घाटे को पाट सकें. यदि बिहार को यह विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करते हुए झारखंड राज्य बनाया जाता है तो यहां की जनता को अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस पैकेज से मिले संसाधन और मेहनती किसान-मज़दूरों के बल पर बिहार बहुत कम समय में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की बराबरी करते हुए न सिर्फ़ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, बल्कि देश के विकास में भी योगदान कर सकेगा.

बिहार के सुनिश्चित आसन्न विभाजन के संदर्भ में आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित समता पार्टी के उक्त अधिकृत ज्ञापन को राजग के संयोजक एवं उसी सरकार के रक्षा मंत्री जी जॉर्ज फर्नांडीस एवं तत्कालीन रेलमंत्री नीतीश कुमार (वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार) के नेतृत्व में संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 26 अप्रैल, 1998 को समर्पित की गई थी, के परिपेक्ष्य में कतिपय प्रासंगिक सवाल उठ खड़े होते हैं, जिसका सीधा संबंध विशेष राज्य का दर्जा की मांग, दावा एवं अभियान से है. उनमें से कुछ का उल्लेख विश्लेषण एवं ख़ुलासा बिहार की जनता की जानकारी के लिए अत्यंत प्रासंगिक तथा आवश्यक है. ये इस प्रकार हैं-

1. समता पार्टी बिहार के विभाजन की न सिर्फ़ हिमायती थी, बल्कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के नेतृत्व ने सर्वसम्मति से इस विभाजन का 1998 में ही अग्रिम स्वागत कर दिया था, जबकि वास्तविक विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ.

2. आज भी विभाजन के बाद बिहार की वही भौगौलिक एवं आर्थिक स्थिति है जो 1998 में थी (वर्तमान सरकार के दावे के अनुसार आर्थिक स्थिति सुधरी है.) तब सीधा प्रश्न उठता है कि विभाजन के संदर्भ के 1998 में समर्पित उक्त अधिकृत ज्ञापन में विशेष दर्जा की मांग एवं दावा क्यों नहीं की गई, जबकि केंद्र की सरकार में समता पार्टी एक प्रमुख घटक था तथा पार्टी के दोनों प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडीस एवं नीतीश कुमार प्रमुख विभागों के केंद्रीय मंत्री थे. जॉर्ज फर्नांडीस तो उस समय राजग के अत्यंत प्रभावशाली संयोजक भी थे.

3. उक्त ज्ञापन में विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा तक नहीं करके दो स्तरों पर आर्थिक पैकेज की मांग की गई थी. इसमें प्रथम स्तर पर पचास हज़ार करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि तथा दूसरे स्तर पर बंटवारे के बाद दस वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 1500 करोड़ की आर्थिक राशि की मांग की गई थी. अब सीधा सवाल यह उठता है कि ज्ञापन 1998 में समर्पित किया गया थी और उसके बाद 2004 के मई तक अर्थात 6 वर्षों से भी अधिक अवधि तक केंद्र में राजग की सरकार रही, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार से भाजपा एवं समता (2003 के बाद जदयू) के कई प्रभावशाली मंत्री थे, तब उक्त ज्ञापन में मांगे गए आर्थिक पैकेज की स्वीकृति क्यों नहीं मिली, जबकि बिहार का विभाजन उसी कार्यकाल में हुआ जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार थी. यहां तक कि संख्या बल के आधार पर 15 नवंबर 2000 को बंटवारे के बाद झारखंड में भाजपा के नेतृत्व की सरकार बन गई, जिसमें समता पार्टी भी सम्मिलित थी. फिर भी 2004 तक केंद्र में राजग की सरकार रहने के बावजूद बिहार को वांछित आर्थिक पैकेज की स्वीकृति नहीं मिली. अब चूंकि इतने वर्षों के बाद जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही राजग सरकार विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर अभियान चला रही है, जिसमें कतिपय समाचार-पत्र एवं पत्रकार भी सक्रिय रूप से शामिल हो गए हैं इसलिए अब जनहित में इस बात का ख़ुलासा करना भी अत्यंत प्रासंगिक एवं आवश्यक हो गया है कि आख़िर विभाजन के संदर्भ में 1998 में दिए गए उक्त अधिकृत एवं सुविचारित ज्ञापन में विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों नहीं की गई थी तथा 2004 तक केंद्र में राजग की सरकार बने रहने के बावजूद उक्त ज्ञापन में की गई आर्थिक पैकेज की मांग क्यों नहीं स्वीकृत की गई. इन दोनों प्रश्नों पर ख़ुलासा इस प्रकार है. काफ़ी विचार मीमांसा के उपरांत तैयार किए गए उक्त अधिकृत एवं सुविचारित ज्ञापन में विशेष राज्य के दर्जे की मांग अथवा दावे की बात तो दूर इसकी चर्चा तक नहीं की गई थी. ऐसा नहीं है कि इस बिंदु पर विचार नहीं हुआ था, किंतु गंभीर रूप से विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया था कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग अथवा दावे की जगह विशेष आर्थिक पैकेज की मांग अधिक व्यवहारिक एवं स्वीकार्य होगी. इसके पीछे तर्क यह था कि विशेष राज्य की मांग की पृष्ठभूमि में संवैधानिक प्रावधानों, भौगोलिक एवं अन्य मापदंडों की संभावित बाधा के अतिरिक्त राजस्थान, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश से भी इसी तरह के दावे एवं मांगें की जाएंगी जो वस्तुत: आज भी की जा रही हैं. अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जब समता पार्टी द्वारा ही विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की गई थी और उस मांग एवं दावे के पश्चात केंद्र में 6 वर्षों से भी अधिक तक राजग की सरकार बनी रही तब आर्थिक पैकेज की स्वीकृति क्यों नहीं मिली. इसकी पृष्ठभूमि में बिहार के राजग मंत्रियों एवं नेताओं विशेष कर बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकारात्मक राजनीति थी. 1998 में झारखंड के आसन्न बंटवारे के संदर्भ में जब उक्त ज्ञापन समर्पित किया गया था तब उस समय की रानजीतिक परिस्थितियों में राजग यह मानकर चल रहा था कि 2000 के विधान सभा चुनाव में राजग की जीत तय है और बाबू लाल मरांडी मुख्यमंत्री होंगे तथा बचे हुए बिहार में समता पार्टी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनेगी, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे. इसी आलोक में नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देकर (संसद से नहीं) मुख्यमंत्री बनने के उद्देश्य से उनके लिए अति सुरक्षित क्षेत्र नालंदा जिलांतर्गत हरनौत से विधान सभा का चुनाव लड़ा. वह अपना चुनाव जीते भी, किंतु विधान सभा चुनाव में अपेक्षित बहुमत नहीं मिला. इसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कतिपय दाग़दार निर्दलीय विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री के लिए राजग द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश किया गया. केंद्र सरकार के परोक्ष सहयोग से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली, किंतु विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया. नतीजतन, कांग्रेस के समर्थन से राबड़ी देवी के नेतृत्व में पुन: राजद की ही सरकार बनी. बिहार में रहकर प्रतिपक्ष की ज़ोरदार राजनीति की घोषणा करने के बावजूद कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार ने पुन: दिल्ली की राजनीति में वापस होकर केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री पद की शपथ ले ली. दूसरी ओर राजग के घोषित निर्णय के आलोक में 15 नवंबर 2000 को बिहार का बंटवारा हुआ, किंतु इस संदर्भ में उक्त समता पार्टी द्वारा समर्पित उक्त ज्ञापन में की गई आर्थिक पैकेज की मांग तथा इसका औचित्य यथावत बना रहा, किंतु जब राजग की सरकार नहीं बन सकी तब नीतीश कुमार सहित केंद्र की सरकार में शामिल बिहार के मंत्रियों एवं नेताओं ने अपने ही द्वारा समर्पित ज्ञापन की मांग के प्रति नकारात्मक रवैया अपना लिया, सिर्फ़ इसलिए कि सत्ता की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में यदि राबड़ी देवी की राजद सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज की राशि एवं अन्य वांछित सुविधा तथा सहयोग मिल गया तब बिहार में विकास की गति में तेज़ी आने की संभावना बढ़ जायेगी और ऐसी स्थिति आगामी चुनाव अर्थात 2005 के चुनाव में भी राजग की जीत तथा नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में बाधा पैदा हो जाएगी. फलस्वरूप राजग नेताओं ने पर्दे के पीछे रहकर बंटवारे के संदर्भ में अपने ही द्वारा मांगे गए विशेष आर्थिक पैकेज एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के प्रति नकारात्मक रवैया अपना लिया. फलस्वरूप पिछड़ा हुआ बिहार विभाजन के बाद साधन एवं सुविधा के अभाव में और पिछड़ता गया. इसे नकारात्मक राजनीति के अतिरिक्त और क्या कहेंगे.

इस अंक में इतना ही. विशेष राज्य के दर्जे की मांग एवं दावे के संदर्भ में संवैधानिक, भौगोलिक व्यवहारिक एवं अन्य प्रासंगिक मापदंडों की पृष्ठभूमि में औचित्य के प्रश्न विश्लेषण अगले अंक में.

लेखक बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य हैं

feedback@chauthiduniya.com

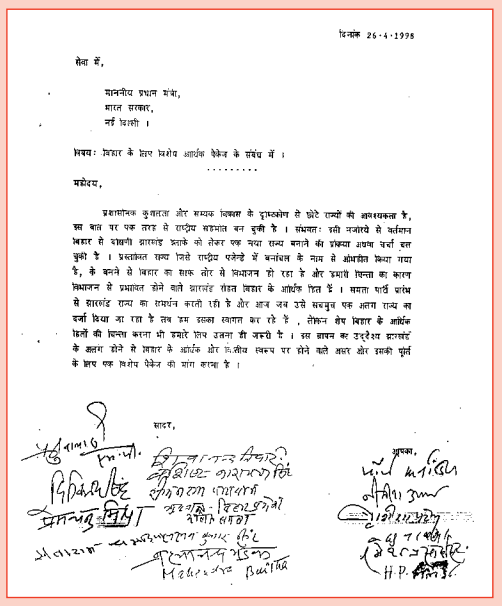

दिनांक 26·4·1998

सेवा में,

माननीय प्रधान मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

विषय: बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज के संबंध में ।

महोदय,

प्रशासनिक कुशलता और सम्यक विकास के दृष्टिकोण से छोटे राज्यों की आवश्यकता है, इस बात पर एक तरह से राष्ट्रीय सहमति बन चुकी है । संभवत: इसी नजरिये से वर्तमान बिहार से दक्षिणी झारखंड इलाके को लेकर एक नया राज्य बनाने की प्रक्रिया अथवा चर्चा चल चुकी है । प्रस्तावित राज्य जिसे राष्ट्रीय एजेन्डे में वनांचल के नाम से अभिहीत किया गया है, के बनने से बिहार का साफ तौर से विभाजन हो रहा है और उसकी चिन्ता का कारण विभाजन से प्रभावित होने वाले झारखंड रहित बिहार का आर्थिक हित है । समता पार्टी प्रारंभ से झारखंड राज्य का समर्थन करती रही है और आज जब इसे सचमुच एक अलग राज्य का दर्जा दिया जा रहा है तब हम इसका स्वागत कर रहे हैं , लेकिन शेष बिहार के आर्थिक हितों की चिन्ता करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है । इस ज्ञापन का उद्देश्य झारखंड के अलग होने से बिहार के आर्थिक और वित्तीय स्वरूप पर होने वाले असर और इसकी पूर्ति के लिए एक विशेष पैकेज की मांग करना है ।

सादर,

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त
हम निम्नलिखित में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं:
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी
मास्टर ऑफ अकुपेशनल थेरापी
मास्टर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक*
मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी*
एम. एड. (स्पेशल एजुकेशन)*
स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम
बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी
बैचलर ऑफ अकुपेशनल थेरापी
बैचलर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक
बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी
बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन)
बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ रेडियोइमेजिंग टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ बायो-टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ ऑफ्थालमोलॉजी
डिप्लोमा पाठ्यक्रम
डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी
डिपलोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी
डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नोलॉजी
डिप्लोमा इन प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक
डिप्लोमा इन हॉस्पीटल मैनेजमेन्ट
डिप्लोमा इन ओ.टी.असिस्टेन्ट
डिप्लोमा इन इ. सी. जी.
सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसींग
डी.पी.टी./डी.ओ.टी. के लिये १ वर्षीय अंडरग्रेड डिग्री इन
फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290, www.iiher.ac.in
Anil Sulabh
Director-in-Chief